stuck in the south through Russia route. Our effort will be to keep trying to bring out anybody who is stuck. I think, again, the House should have that assurance. The question raised was: Does this qualify as evacuation? The advisory which we issued initially was advisory urging students and all Indian nationals to go back. But, after February 2024, we started sending planes, our civil aircraft, military aircraft; we started deputing people and we started running camps. One issue was that we were not present in the conflict areas. I would like to correct you. We were. Our officers actually went even into Sumy; there were people outside Sumy. The first set of people that Indian students saw when they came out of Sumy was our officers. I think we should be correct on facts and we should give credit that is due. So, I would say, please understand that this is a very large country. Obviously, when the war started, there was martial law; there were restrictions on movement. Within these constraints, I think, the embassy, the officers who were deputed and all the other organisations including the volunteers and the civil society representatives did all that they could. So, again, I would urge all the hon. Members to recognise the efforts made in this operation. Finally, regarding the concern which many hon. Members expressed about the future of the students, I would say that they have just come back. We have to see what happens in the situation, including the online classes issue that we were addressing earlier. But I cannot say anything more. It is not directly my remit. But I assure you that the Government will approach this matter with fullest sense of responsibility.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over now. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Ram Vichar Netam to raise the discussion on the working of the Ministry of Tribal Affairs.

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): उपसभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण जनजातीय कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित माँगों के सम्बन्ध में मुझे अपनी बात रखने की जो अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, यदि हम देखें तो पूरे देश में हमारी पूरी ST population लगभग 22 करोड़ है। इस देश में बहुत सारे ऐसे प्रदेश भी हैं, जहाँ शत-प्रतिशत ST population है। North-East के सम्बन्ध में आज ही सदन में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हुई है। इसी प्रकार से जो सबसे अधिक tribal base वाले प्रदेश हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा हैं और इनके साथ-साथ अन्य बहुत सारे प्रदेश हैं - North-East में तो

अधिकांशतः सभी tribal states ही हैं। वहां की करीब शत-प्रतिशत जो जनसंख्या है, आरक्षण है, वह tribals है। इसी प्रकार से देश के अन्य राज्यों में भी चाहे वह राजस्थान हो, कर्णाटक हो, गुजरात या अन्य ऐसे कई राज्य हैं, जहां पर कम संख्या में tribals हैं, लेकिन फिर भी वहां पर tribals की संख्या तो है। देश की आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार इस वर्ग के लोगों को यह महसूस हुआ कि हमारा संरक्षण करने वाला, विकास करने वाला, हमारी जो विस्थापन की समस्या है, जिस विस्थापन की मार को इस समाज ने सदियों-सदियों तक झेला है, उसे अब समझ में आया है कि हमारे दर्द और तकलीफ को यदि कोई दूर कर सकता है, तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। इसलिए यदि वर्ष 2014 की बात करें, तो वर्ष 2014 में देश में जिस प्रकार का परिवर्तन आया उस परिवर्तन को करने के लिए देश के मानस ने एक मन बना लिया था कि चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम लोगों को बहकाने के लिए जो तरह-तरह के बहुरूपिया लोग आते हैं, उनके बहकावे में हमें न आकर, जो हमारी चिंता करने वाले लोग हैं, हम उन्हें वोट देंगे और यही कारण है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री पर लोगों ने विश्वास किया। आज उनका नेतृत्व और कर्तृत्व हम सब देख रहे हैं। उन्होंने देश के लिए पूरा जीवन समर्पित करने का निर्णय किया है। उन्होंने दीन, दलित, गरीब, दुखिया, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों की चिंता करते हुए, हमारे सुदूर अंचल में रहने वाले आदिवासी लोगों की चिंता करते हुए, जिस प्रकार से अनेक योजनाएं चलायीं, उनकी बेहतरी के लिए कि उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सके, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे लाया जा सके, इन सभी बातों की चिंता करते हुए जिस प्रकार से योजना बनाकर काम करना शुरू किया, उसका ही नतीजा है कि 2014 के बाद यदि 2019 की बात करें तो 2019 में भी हमें सफलता मिली और अभी 2022 में भी लोगों ने जो रिजल्ट दिया है, वह सबके सामने है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) *पीठासीन हुए*]

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह कोई दिखावा नहीं है। कहा जाता है कि मुखिया कैसा होना चाहिएः- 'मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहुं एक, पालइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित बिबेक।' महोदय, यह देश इस समय का न जाने कब से इंतजार कर रहा था और वह नेतृत्व 2014 में इस देश को मिला, जो कि आज हम सबकी चिंता करने वाला है। महोदय, किसने सोचा था कि गरीबों के घर पक्के हो जाएंगे। किसने सोचा था? बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया था, वे लोग क्यों नहीं कर पाए? उनकी तो कागजों में बिल्डिंग्स बन जाया करती थीं, कागजों में नल लग जाया करते थे! उस समय के प्रधान मंत्री जी ने इस बात को इंगित किया था कि हम यहां से 100 रुपए भेजते हैं लेकिन 88 रुपए पाइप में ही रह रहे हैं, यह स्थिति है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उस दल के उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने ही यह कहा था लेकिन वर्तमान प्रधान मंत्री जी पर हम सबको, देशवासियों को गर्व होता है, जो यदि 100 रुपए भेजेंगे, तो 100 रुपये पहुंचाकर हिसाब भी लेंगे। यह उनका कर्तृत्व है और यह उनका नेतृत्व है। उसी का यह परिणाम है कि आज पूरे देश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज गरीबों के घर में भी बिजली है, उनके कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बन रहे हैं। आज गरीब के बच्चे भी अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, एकलव्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं। यह विद्यालय एक समय में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से बनते थे,

लेकिन वर्तमान में उसको revise करके, जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए उसे बढ़ा कर 38 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब वे 38 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। ये सब काम ऐसे विराट व्यक्तित्व, ऐसे करिश्माई नेतृत्व वाले प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। आज इनके नेतृत्व में देश जिस तरह से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसके कारण दुनिया में भारत का, इस देश का डंका बज रहा है। इस बात के लिए हम सबको गर्व होना चाहिए, लेकिन जब हमारे विपक्ष के साथीगण इस तरह से comments करते हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तरह-तरह की आलोचनाएँ करते हैं, तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। वे आलोचना करें, लेकिन सकारात्मक आलोचना करें। अगर काम हो रहा है, जिसके कारण आज देश का नाम हो रहा है, देशवासियों का स्वाभिमान बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि हम सबको इसके लिए दाद देनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए, शुभकामना देनी चाहिए, लेकिन पिछले 5-6 सालों में मुझे यह नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला कि कभी ये सब सरकार के समर्थन में आगे आकर बोले हों, जबकि एक से बढ़कर एक काम हुए हैं।

महोदय, आज उन गरीबों के गाँवों, गलियों तक पक्की सड़कें बन गईं, हर गाँव के हर मोहल्ले तक 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत चमचमाते हुए आवास बन रहे हैं, उनके घरों में भी शौचालय बन रहे हैं, उनके घरों में बिजली लग रही है। अभी चुनाव के दौरान जब मैंने सोनभद्र के सुदूर अंचल में देखा कि वहाँ गाँवों में वाटर सप्लाई के लिए बड़े-बड़े पम्प लग रहे हैं, टंकियाँ लग रही हैं, तब मैंने वहाँ पर लोगों से पूछा कि क्या बात है, तो वे बोले कि यह मोदी जी की देन है। उन गरीबों से पूछा कि क्या बात है, तो वे बोले कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो देख रहे हैं। हमारा देने वाला दाता और भगवान स्वरूप माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसकी वजह से ही हम जी रहे हैं, खा रहे हैं। आज उन गरीबों की चिंता करने वाला अगर कोई है, तो वह माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। इस वैश्विक महामारी की चपेट में पूरा देश और दुनिया तबाह हो गयी, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की तरह, फरिश्ते की तरह अगर किसी ने खड़े होकर इन गरीबों की चिंता की, तो वह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी वाली सरकार ने की। मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में इस ट्राइबल विभाग में एक से एक योजना चला करके एक से एक परिवर्तन करने का काम हो रहा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के तमाम साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं।

महोदय, आज हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हो रहे हैं। मैं बजट के बारे में बहुत लंबी-चौड़ी बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन लाने, नौजवानों में जोश भरने, नई शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उन्हें बेहतर शिक्षा की ओर ले जाने का सपना देख करके माननीय अर्जुन मुंडा जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

महोदय, बहुत सारी बातें हैं। चाहे झारखंड में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, इन राज्यों में बहुत सारे ऐसे भी समाज हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, जिनको आज भी एसटी का दर्जा नहीं मिल पाया है। उस दिशा में भी हमारे माननीय मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी उन्हें बधाई देना चाहूँगा।

महोदय, यही नहीं, बल्कि आज देश को जिस प्रकार एकलव्य मॉडल दिया है, उसका बेहतर निर्माण करके, वहाँ बेहतर प्रबंधन करने की जो व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज हमारे समाज में, सुदूर अंचल में परिवर्तन हो रहे हैं। चाहे नॉर्थ-ईस्ट की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, ये क्षेत्र पिछले कई वर्षों से नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं।

4.00 P.M.

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उन सुदूर अंचलों में, जो ट्राइबल बेस्ड जिले हैं, वहाँ पर कानून कैसा चल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है, किस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, किस प्रकार की शिक्षा है, डेवलपमेंट के तमाम काम कैसे चल रहे हैं, केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है, इन सभी को निर्धारित किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में लगभग 100 Aspirational Districts का सेलेक्शन करके, उनकी विशेष निगरानी करके, वहाँ पर विशेष ध्यान देकर डेवलपमेंट के कामों को और बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, मैं इसके लिए भी माननीय प्रधान मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें बधाई देते हुए, माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए, अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : छाया जी, आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** श्री नारण भाई जे. राठवा।

श्री नारण भाई जे. राठवा (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण जनजातीय मामलों के मंत्रालय की अनुदान माँगों पर चर्चा हेतु समय दिया है। मैं सदन में यह दुख के साथ कहना चाहूँगा कि इस बजट में दलित और आदिवासियों को न सिर्फ उनके आर्थिक हक से वंचित रखा गया है, बल्कि उन्हें बजट से अदृश्य ही कर दिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटित की गई अनुदान राशि बहुत ही निराश करने वाली है। इसमें नीति आयोग के दिशानिर्देशों तक का पालन नहीं किया गया है, जिसमें दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में हिस्सेदारी तय किये जाने की व्यवस्था है। इस बजट में आदिवासियों और दलितों को लाभ पहुंचाने वाली किसी भी योजना को या तो सिरे से ही गायब कर दिया है या पूरी तरह से अप्रासंगिक कर दिया गया है। वर्ष 2022-23 के केन्द्रीय बजट को कॉरपोरेट सेक्टर का बजट कहना बिल्कुल उचित है। दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान ने इस वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय बजट में अपने विश्लेषण में इस बात पर प्रकाश डाला है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए नीति आयोग के निदेशों के अनुसार आवंटन करना अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान केन्द्रीय सरकार पिछले सात वर्षों से जनसंख्या के अनुपात में इस अनिवार्य राशि के आवंटन की अनदेखी करती रही। दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के मुताबिक एससी-एसटी समुदायों के लिए बजट में क्रमशः 40,634 करोड़ रुपये और 9,392 करोड़ रुपये का अंतर है। अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित वर्ष

2021-22 में वह 79,942 करोड़ रुपये से बढ़कर 87,473 करोड़ रुपये हो गया है और इस 2022-23 में बढ़कर वह 89,265 करोड़ रुपये हो गया है, जो सरकार के पूरे बजट का 2.26 परसेंट है। एसटी समुदाय देश की कुल आबादी का लगभग 8.8 परसेंट है। इसी तरह, वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति के लिए 1,26,259 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो अब संशोधित बजट में बढ़कर 1,39,956 करोड़ रुपये हो गया है और इस वर्ष 2022 में यह फिर से बढ़कर 1,42,342 करोड़ रुपये हो गया, यानी सरकार के पूरे बजट का 3.61 परसेंट, जबकि अनुसूचित जाति समुदाय देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.2 परसेंट है। महोदय, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2022-23 में फसल बीमा योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए 1,381 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। इसी तरह, अनुसूचित जाति के लिए इस योजना में 2,667 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर, केन्द्रीय बजट 2022-23 में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए धन आवंटन को कम कर दिया गया है। साथ ही, बजट में कृषि शिक्षा, पशु विज्ञान, फसल विज्ञान एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर होने वाले खर्च को कम किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार के पास पिछले वर्षों में इस योजना के तहत आवंटित धन के बारे में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लाभार्थियों का कोई डेटा नहीं है, इसलिए यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने एससी/एसटी लाभान्वित हुए हैं।

इस वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय बजट में अनुसूचित जनजाति हेतु रोजगार सृजन के लिए आवंटन में भी भारी कमी हुई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन पिछले वर्ष के 7,524.85 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 12.32 प्रतिशत बढ़कर 8,451.92 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन दूसरी ओर, केन्द्रीय बजट 2022-23 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में इस साल 11.3 करोड़ रुपये की गिरावट आई है, जो पिछले साल 89.5 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति हेतु रोजगार सृजन के लिए आवंटन पिछले वर्ष के दौरान 170.96 करोड़ रुपये से काफी कम होकर 22.97 करोड़ रुपये हो गया है।

महोदय, यह दुःख की बात है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रम कल्याण योजना में इसे विगत वर्ष में 12.9 करोड़ रुपये से घटाकर 10.66 करोड़ रुपये किया गया है। इसी तरह, अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन के तहत पिछले वर्ष के 24.9 करोड़ रुपये को घटाकर 19.88 करोड़ रुपये किया गया है। वर्ष 2022-23 के बजट में प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना - 'मनरेगा' के लिए केन्द्र ने 73,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जो पिछले वर्ष इस योजना के लिए 98,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 25 परसेंट कम है। यह किसी से भी छिपा नहीं है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय गारंटीकृत सरकारी काम और भुगतान के लिए 'मनरेगा' पर ही निर्भर हैं। इस संबंध में मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि इस आवंटित राशि से ही मजदूरी के रूप में 1,464 करोड़ रुपये और सामग्री के रूप में 10,900 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है, जो बजट को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि नए बजट में केवल 60,700 करोड़ रुपये ही प्रभावी रूप से उपलब्ध होंगे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि केन्द्र की भाजपा सरकार की प्राथमिकता दलित आदिवासियों के लिए नकारात्मक साबित हो रही है तथा इस बजट के जरिए

भाजपा सरकार ने यह साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकता में न तो आदिवासी हैं और न ही दलित हैं। मुझे दु:ख के साथ इस सदन में यह कहना पड़ रहा है कि केन्द्रीय सरकार देश के कमजोर, दुर्बल आदिवासी लोगों के कल्याण हेतु समय-समय पर अनेक योजनाएँ घोषित करती रही है, लेकिन तत्परता के साथ उनका क्रियान्वयन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से देश के गरीब, आदिवासी और दलित लोग अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं।

जो infrastructural gaps हैं, ढांचागत सुविधा का जो अभाव है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ढांचागत सुविधा का अभाव बहुत ज्यादा है। गत वर्ष की स्थिति के अनुसार, अभी 10 किलोमीटर के दायरे में 39,786 गाँवों में बैंक की सुविधा नहीं है और 39,513 गाँवों में एक गाँव से दूसरे गाँव तक सड़कों का जुड़ाव नहीं है। उपसभाध्यक्ष महोदय, 50,533 गांवों में सीसी और ब्रिक रोड्स नहीं हैं; 34,999 गांवों में परिवहन की सुविधा नहीं है; 97,085 गांवों में इंटरनेट और कॉमन सर्विस की सुविधा नहीं है; अभी 7,176 गांवों का विद्युतीकरण होना बाकी है; 90,100 गांवों में मार्किट की सुविधा नहीं है; 61,656 गांवों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना बाकी है; 17,538 गांवों में लैंडलाइन या मोबाइल फोन की सुविधा उपलबध नहीं है; 1,20,84,884 आदिवासी घरों में एल.पी.जी. और बायोगैस की सुविधा नहीं है; 91,14,133 आदिवासी लोगों के घरों की दीवारें और छत भी कच्ची है; 13,501 गांवों में एक भी स्कूल नहीं है, ये गांव बिना स्कूल के हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि 28,031 गांवों में 10 कि.मी. के दायरे में दवाखाना और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं है; 42,412 गांवों में 10 कि.मी. के दायरे में वेटरनरी क्लीनिक्स भी नहीं हैं और 58,063 गांवों में ड्रेनेज का सिस्टम भी नहीं है। देश के अंदर ऐसे बहुत-से गांव हैं, जहां पर इन सभी सुविधाओं का अभाव है। मैं 'एकलव्य मॉडल स्कूल' के बारे में बताना चाहता हूं। अभी मेरे पूर्ववक्ता बता रहे थे कि 'एकलव्य मॉडल स्कूल' चालू किया गया, लेकिन मॉडल स्कूल के अंदर qualified teachers नहीं मिलते हैं। वहां पर Chemistry, Physics, Biology, English and Science के subject-wise teachers स्कूल्स में उपलब्ध नहीं हैं। वहां पर 35-40,000 करोड़ के बड़े-बड़े एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय बना दिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' के नाम पर अलग-अलग जगहों पर, खासकर ट्राइबल एरियाज़ में एकलव्य विद्यालयों में टीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से वहां पढ़ाने में दिक्कत आती है। उसके साथ-साथ वहां स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स की बिल्डिंग्स की हालत बहुत जर्जर है और उनके अंदर जो सुविधा होनी चाहिए, वह सुविधा वहां पर नहीं है। अभी sports के बारे में बात हो रही थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर sports के teachers नहीं हैं और drawing के teachers भी नहीं हैं। आप लोग 'खेले गुजरात, जीते गुजरात' की बात करते हैं, लेकिन वहां पर पढ़ाने वाले एक्पर्ट टीचर्स नहीं हैं। इससे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूं कि इसी तरह से आदिवासी एरियाज़ में जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही हैं। उसके साथ गांव के हॉस्पिटल्स में यह देखते हैं कि वहां पर सिस्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, वहां विभाग-वार pediatrician, MD (Medicine) डॉक्टर्स नहीं हैं, surgeons नहीं हैं और anaesthetists भी नहीं हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह पूरा जनजातीय मंत्रालय है। सर, जनजातीय मंत्रालय जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले लोगों का गांव होता है। उन लोगों के गांवों में

स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है। यदि irrigation करना है, तो आदिवासी विस्तार के लोगों को irrigation की भी कमी है। वहां सरदार सरोवर डैम है, जिसको नर्मदा डैम भी बोलते हैं। उसकी मेन canal से राजस्थान के गांवों और सौराष्ट्र के अंदर पानी जाता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि किनारे पर रहने वाले आदिवासी लोगों को lift irrigation करके वहां पर पानी देना चाहिए। हमारे गांव में से canal जाती है, लेकिन canal के आस-पास रहने वाले खेडुत लोगों को सिंचाई का पानी, irrigation का पानी नहीं मिलता है। उसके साथ-साथ अभी वहां पर दूसरी प्रॉब्लम भी हो रही है। जब भी सिंचाई डैम बनता है, तो उसमें आदिवासी लोगों की ज़मीनें जाती हैं, जिससे आदिवासी लोग बेघर हो जाते हैं। उनके लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने गुजरात में वघई रिवर लिंक प्रोजेक्ट की घोषणा की। वहां पर डैम के अंदर हंगामा चल रहा है, जिससे आदिवासी लोगों को नुकसान होने वाला है। वहां पर उसको फायदा नहीं हो रहा है। अभी वहां पर एजिटेशन चल रहा है। ये वघई रिवर लिंक प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही 2005-06 में आदिवासी लोगों को जंगल का पट्टा देना था, वह लगभग एक लाख लाभार्थियों का बाकी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार के अंदर यह घोषणा की गई थी और जो आदिवासी लोग वहां पर illegal cultivation करते थे, उनको 2005-06 के अंदर पट्टा देने की बात कही गई थी। वह नहीं दिया गया है और जिसको दिया है, सात-आठ बार नकल के अंदर उसकी नौंध नहीं हुई है। उसके साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आप कह रहे हैं कि वहां पर नेट उपलब्ध नहीं है। वहां पर बीएसएनएल टावर नहीं है। इन्होंने बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की बात कही है। अभी कोविड-19 के अंदर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की बात चली थी। वहां पर आदिवासी लोगों के पास जो मोबाइल फोन होता है, वह सादा फोन होता है। उनके पास android phone नहीं होता है और इतना महंगा फोन वहां कोई नहीं रखता है। वहां हर गांव में बीएसएनएल टावर की सुविधा होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि पूरे देश के अंदर और गुजरात के अंदर जितने रिमोट एरियाज़ हैं, वहां बीएसएनएल टावर की सुविधा दी जाए, ताकि हमारे बच्चों को और जो लोग भी गांव में सर्विस करते हैं, जैसे एएनएम नर्सेज़ हैं, टीचर्स हैं, तलाटी हैं, उन लोगों को भी आने-जाने और कम्युनिकेशन की सुविधा मिलनी चाहिए।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) *पीठासीन हुए]*

उसी तरह 'वन धन योजना' भी बनाई है। उसके अंदर खेडुतों को अनाज का डबल भाव मिलना चाहिए, जो कि उसे नहीं मिल रहा है। आप लोग कहते हैं कि वहां पर डबल भाव मिलेगा, लेकिन महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि उसके अंदर उसको फायदा नहीं हो सकता है।

इसी प्रकार से अगर रोजगार की बात करें, तो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर बहुत से पढ़े-लिखे लोग हैं, जैसे ग्रेजुएट हैं, डबल ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। महोदय, मैं आपके जरिए भारत सरकार से, होम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से डिमांड करता हूं कि हमारे एरिया से मध्य प्रदेश बॉर्डर लगता है, राजस्थान बॉर्डर लगता है, महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है, वहां पर बिरसा मुंडा रेजिमेंट खोली जाए। गरीब आदिवासी लोग बहुत मजबूत होते हैं, वे शारीरिक दृष्टि से बहुत ताकत वाले लोग होते हैं, तो वहां पर बिरसा मुंडा रेजिमेंट बनाएं और वहां पर

आदिवासी लोगों को रोज़गार का एक अवसर मिले, देश की सेवा करने का अवसर मिले, यह भी मेरी डिमांड है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे ट्राइबल एरिया के अंदर जितनी भी रेलवे लाइन्स जाती हैं, रेलवे लाइन्स के अंदर जो भी प्रोजेक्ट sanction हुआ है या जो भी काम चल रहा है, वह समय-सीमा के अंदर खत्म नहीं होता है। अभी गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश और गुजरात की सरहद को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन चालू है, उसे 2012 में पूरा करना था, गरीब आदिवासी लोगों और मजदूर लोगों का वहां से मजदूरी के लिए पलायन होता है। वहां पर माइग्रेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए, उनके लिए सरल मुसाफिरी करने के लिए, उनको कम भाड़े में मुसाफिरी करने के लिए रेलवे का जो प्रोजेक्ट चलता है, उसके अंदर ज्यादा फंड देकर रेलवे प्रोजेक्ट का काम जल्दी खत्म करें। इससे आदिवासी लोगों के लिए आने-जाने की सुविधा होगी।

दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिजली की है। आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को रात में बिजली देते हैं, दिन में उन्हें बिजली नहीं मिलती है और बिजली बहुत महंगी है। पूरे इंडिया के हमारे सभी लोग including गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो जंगल में रहते हैं, वहां पर जंगली जानवर का भी खतरा रहता है और रात को चोरी, लूट-पाट भी होती है। वे वहां पर खेती कैसे करेंगे? देश के अंदर जो भी tribal areas हैं, उसके अंदर बिजली रात की बजाय दिन में मिलनी चाहिए, यह भी हमारी मांग है। जितने भी खेडुत लोग हैं, वे दिन में काम करें। Industries वालों को रात में बिजली देनी चाहिए। उद्योगपतियों को तो, चाहे वे रात को चलाएं या दिन में चलाएं, उनको कोई problem नहीं होती है। वहां पर खेडुत लोगों को रात में बिजली क्यों देते हैं? बिजली इतनी महंगी कर दी है कि खेडुत लोगों के लिए बिजली लेना भी मुश्किल कर दिया है। हमारी जो ट्राइबल लोगों की डिमांड है, उसे ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करें। पूरे देश के अंदर जितने भी tribal areas है, वहां पर सुविधा देने का काम करें। अभी माननीय सदस्य 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छी बात है कि 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' सैंक्शन हुई है, लेकिन पर्यावरण के नाम पर फॉरेस्ट एरिया वाले जो भी ऑफिसर्स हैं, वे परमिशन नहीं देते हैं। इसीलिए 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' का काम आज भी ढीला पड़ा हुआ है। वहां पर रोड बनाने के लिए जल्दी मंजूरी मिल सके, इसके लिए पर्यावरण विभाग से सम्पर्क करना चाहिए। आदिवासी एरिया में, ट्राइबल एरिया में 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत जो रोड्स बननी हैं, उनको बनाने के लिए जल्दी से जल्दी मंजूरी दी जाए, यही हमारी डिमांड है।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जंगल की ज़मीन की सनद देने का काम 2005-06 में शुरू किया गया था, इस काम को भी तुरंत करवाने के आदेश भारत सरकार की तरफ से हरेक राज्य में जाने चाहिए, ताकि लोगों को जंगल की ज़मीन का पट्टा मिल सके। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। साथ ही मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): धन्यवाद राठवा जी। श्री अबीर रंजन बिस्वास ।

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, thank you for giving me this opportunity. There are 23.5 per cent Scheduled Castes and nearly 6 per cent Scheduled Tribes in my home State of West Bengal. According to 2011 Census reports, the STs literacy rate in India, in males it was 68 per cent and in females, it was 49 per cent respectively. The West Bengal STs literacy rate was 74 per cent and 43 per cent, respectively, for males and females. Under the able-leadership of our Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, we successfully run the SC/ST pension schemes namely, Joy Johar, Tapasili Bandhu, Joy Bangla, all these are there to take care of the elderly communities amongst the SCs and STs. We know that, actually, they are the most marginalized sections of the society and, especially, the tribals, they are very poor, marginalized, socially also, they are downtrodden. So, the Bengal Government has taken into account all these things. The Government, especially, looking into plight, at times, of elderly people of these marginalized sections and has provided a monthly pension of Rs. 1,000 to give them a cushion of comfortability, financially and also socially. So, their social security is also taken care of, and in this way, we have tried as much as we could do to stand beside these marginalized communities. Further, we have also established various lending programmes to help grow entrepreneurship in these communities. However, matters at the national level require a serious inquiry.

As per the 2011 Census, 8.6 per cent of the country's total population is Scheduled Tribes. Of the total primary school students population, you will see that the dropout among the tribal students is maximum. That is most unfortunate. In the working population, if you see the representation, it is only 6 per cent of those employed in Government offices who come from this Scheduled Tribe section.

Again, it is not pro-rata. In spite of the constitutional mandates and the safeguards that have been provided, we have failed to deliver on the promises and we have failed to accommodate our ST population as was mandated by the Constitution. These things need to be looked into seriously.

According to the Ministry's Gap Analysis Dashboard of villages where the ST population is greater than 25 per cent, you will be astonished to know that only 9 per cent of these villages have banks, only 24 per cent of these villages have a healthcare centre and even more alarming, only 50 per cent have tap water and drainage facilities. As recently as in February, 2022, there was a very alarming situation in a particular case of a tribal community in Jammu's Doda district. We are spending so much on works in Jammu & Kashmir. We are thumping our own backs of what we have done in Kashmir and how we keep on lauding ourselves but what have we done? Whereas if you see the STs, they are larger in figures than the SCs there. They

are nearly 10 per cent. In one particular case, we found that a tribal community in Jammu's Doda district was compelled to spend their own savings in order to gain access to potable water in the village. There is no drinking water. They spend their own savings and get water. The people of ST community in Jammu, mainly the Bakkarwals and such people, are the most marginalized people in the whole country. So they had to spend their own savings to arrange water. Even in the overwhelmingly advertised vaccination drive, a majority of the bottom 50 districts in terms of vaccine coverage have sizable tribal population, that is, 72 per cent of this population is from rural, tribal majority districts. Sir, real work has happened in Bengal and some other States. In the spirit of federalism, we must take some of these ideas and implement them further for greater cause of the nation. This Government should shed its arrogance and take a leaf out of book of Ms. Mamata Banerjee, the Chief Minister of Bengal, who has done well, as I have said. In this year's Budget, the Ministry had proposed an amount of Rs.13,208 crores in the Budgetary Estimates for 2022-23 under various Centrally-Sponsored Schemes and Central Sector Schemes, out of which the Ministry of Finance has provided only an amount of Rs.8,406 crores, that is, there is a 36 per cent slash. In the years 2020-21 and 2021-22, the Ministry of Tribal Affairs had an allocation of Rs.7,355 plus crores and Rs.7,084 crore respectively. However, the allocation was reduced to Rs.5,472 crores in 2020-21 and Rs.6,126 crores in 2021-22 at the Revised Estimate stage. What is most shocking is that the Ministry of Tribal Affairs could not even fully spend the Revised Estimate allocation in 2020-21 and have been able to utilize just Rs.4,070 crores in 2021-22 up to 15th February, 2022, which is most alarming.

Under-utilization of funds is a serious problem and we need to look into this. The under-utilization of funds is also reflected in two Special Area Programmes administered by the Ministry. Only half of the total allocated Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme was utilized in 2020-21. For the year 2021-22, the allocated amount was Rs. 1,350 crores, of which just a paltry sum of only Rs.4 crore had been utilized till January. It is unimaginable. Why this massive shortfall? On top of this, in grants-in-aid, out of Rs.1,350 crores of grants-in-aid for 2021-22, only Rs.364 crores have been utilized so far. Again, it is very alarming. The Standing Committee on Social Justice and Empowerment too observed and I quote "The Ministry of Tribal Affairs should avoid rush of expenditure at the fag end of the financial year and make sincere efforts so that funds are timely spent and the targeted people get the benefits." The Standing Committee on Social Justice and Empowerment in its 30th Report has pointed out the stagnation in the scholarship programmes offered to ST students. Under Pre-Matric Scholarship Scheme, the beneficiaries of the funds

released in some of the States such as Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Meghalaya, Puducherry, Telangana and Uttar Pradesh are alarmingly shown as nil. Of course, I do not know and the Minister will clarify this. Sir, 750 national fellowships are provided to the ST students each year for pursuing higher studies. During the last five years, only 45 students have been awarded the National Overseas Scholarship. Even 20 scholarships are not being fully utilized. The Standing Committee also found that overseas scholarship of 55 tribal students lapsed in the last five years due to the irresponsible approach of the Government. Out of the sanctioned amount of Rs.5 crore for overseas scholarship, most unfortunately, only little over Rs.2 crore has been spent for the year 2021-22. The Committee noted that for most of these scholarships, the number of beneficiaries and funds allocated has not increased over the year. The recommendations that the Committee has put is, I quote: "The annual increase in tribal population should be taken into consideration at the time of budgetary allocation and it should also be ensured that the number of beneficiaries increase every year." The Parliament must note with urgency that the National Commission on Scheduled Tribes is short staffed and that the Reports of the Commission since 2018 are still under process in the Ministry of Tribal Affairs and have not been presented to the Parliament till date. In light of all these facts and figures, I urge the House to unite for a sincere discussion focussed on the welfare of the Scheduled Tribes. I would like to end by saying, in this 75th Year of Independence, that any progress, that does not include all its citizens, is not a progress because at this point in time, in the global scenario, whenever we talk of anything, we talk of inclusiveness and especially, in the Indian context, if you really want to surge ahead, move ahead, if you are not taking on board all the marginalized sections, this progress will only be a limited progress and ultimately, this will not allow you to achieve the goals you are dreaming of by saying, '*Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas*'. Sir, this should not merely remain as a statement of the Government. It should reflect on the ground. It should be palpable. We should be able to feel it. The marginalized communities should be able to have the advantage of it and we should be more careful that at any future point in time, the history does not denote this as a mere *jumla*. Thank you, Sir.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Hon. Vice-Chairperson, Sir, the Union Government has earmarked a Budget outlay of Rs.8,451.92 crores for the Ministry of Tribal Affairs. It is just an increase of 12.32 per cent from the last year. Rs.7,524.87 crores were sanctioned in the year 2021-22. This amount, when compared with the growth of tribal population in various States is not adequate for the overall

development projects. I would like to highlight two points from the Demands for Grants, 2022-23. I completely agree with the vision and intention of the Ministry to promote the livelihood of Scheduled Tribe community, particularly, women and other vulnerable groups. First, I would like to invite attention to the educational programmes and incentives. In 2022 Union Budget, the National Scheme for Incentive to Girl Child for Secondary Education (NSIGSE), which was started in 2008-09 to promote the enrolment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe girls in secondary schools and reduce the dropout rate among them, has been discontinued. Under the NSIGE, a fixed deposit of Rs.3,000 was made in the name of each beneficiary on her enrolment in Class IX. The girl was entitled to withdraw the sum along with the interest after turning 18 provided she had cleared Class X and was unmarried. If there was any reason behind the discontinuing of this scheme, can the Department elucidate on this? Drop-out rate among school children has increased during Covid. Many students from marginalized communities have been compelled to stay out of schools and support their parents in their forest-based land, local livelihood. Was this situation assessed and is there a correlation behind discontinuing the NSIGSE scheme and improving their intake in schools? Secondly, for this year 2022-23, the Union Government has introduced capital expenditure on setting up a venture capital fund for Scheduled Tribe at Rs.50 crores. The scheme was to be a social sector initiative to promote ST entrepreneurship and to support and incubate the start-up ideas by ST youths. In addition to this, a new scheme for development of tribal entrepreneurships in North-East called 'Logistics and Marketing of Tribal products in North East' has been approved and an amount of Rs. 75 crores has been earmarked for it. These could have been valuable initiatives had there been some feasibility study and report to support the Budget. The lockdowns were characterized by several factors that put India's 6.33 crore Micro, Small and Medium enterprises in jeopardy-closure of the mandis and the wholesale markets, transport restrictions, disruptions in supply chain and lack of procurement. The sudden announcement of lockdown measures, left them without their usual sources of income. The resulting financial insecurity had knock-on effects on the safety, health and education of these communities. During the lockdown, instances of forest land diversion defied the Act, where the Environment Ministry had given clearance to eleven projects across the country and issued new guidelines for relaxing forest and environment clearance norms for mining by new leases (MoTA, 2020). Some of these projects that required forest diversion were allowed without consulting the Gram Sabhas. Against this background, how do we explain the two new schemes to benefit the tribal community? Sir, Eklavya Model Residential Schools (EMRS) have a total financial

outlay of Rs. 28,920 crores and Pradhan Mantri Van Bandhu Kalyan Yojana have total financial outlay of Rs. 26,135 crores for their continuation till 31.03.2026. It is unfortunate that Tamil Nadu has got just 7 Eklavya Schools. I would request the hon. Minister to allocate more schools to Tamil Nadu. A total of Rs. 2000 crores have been sanctioned for setting up EMRSs in the Budget of 2022-2023. Sir, the scope of existing scheme of SCA (Special Central Assistance) to TSS (Tribal Sub Scheme) has been broadened wherein comprehensive development of 36,428 villages will be undertaken in convergence with line Ministries to develop these villages as Adarsh Gram under Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana. These villages have tribal population of more than 500 and fifty per cent of its population is tribal people. My question is, do we actually adopt all these Adarsh villages under this Yojana? We need a clear answer from the hon. Minister.

Sir, one point is about discontinuation of education programme for girls from tribal community. Learning deficit had already increased drastically and many have dropped out of schools and taken up some job to sustain their livelihood. How discontinuance of a targeted intervention programme resolve this issue? The other point is regarding two schemes that claim to promote entrepreneurship among tribal communities. Essentially, the poverty rate among the tribal groups is grave and Covid pandemic has pushed them into deep neck financial stress. Some of the rural and urban women small vendors have given up businesses and taken up street vending. No package was carved out as a part of Union Government's sector-wise Covid relief. How will these two schemes that have not provided any gradual relief aim to magically identify target communities and formulate a policy for institutions to make the scheme effective? A similar programme venture capital found for SC is found to be under-utilised as there are not many takers. In 2017-18, there is nil utilization in this scheme. How can the new scheme avoid the redundancy? Was there any baseline study done, any consultations with the community undertaken, any experts, including civil society have offered recommendations? Can we get more information, and on how the Department will implement this scheme targeting STs with effectiveness?

Sir, some of the Government schemes which have been implemented need to be monitored properly and purposefully. One is, the Eklavya Model Residential Schools need to be implemented throughout the tribal areas of this country. The pending dues to Tamil Nadu under the post-matric scholarship and pre-matric scholarships for STs have to be paid immediately. Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution, require to be done in seven Districts of Tamil Nadu where tribal people live in sizeable numbers. Marketing and logistics facilities have to be implemented all over the country to help the tribal people. Development for promoting

tribal products from North-Eastern region requires more focus as most of the population in North-Eastern States belongs to the tribal communities. Usually the Adivasi women depend on minor forest products like timber, forest medicine, honey, gooseberry, tree gum, fruits, kendu leaves and sal seeds. Once upon a time all these resources such as hills, mountains, land, water and forests belonged to the *Adivasis* and they used to survive in coexistence with nature. Their self-sufficiency was dependent on these resources. Now all these are under the control of the Government and private owners. The *Adivasis* have lost their self-sufficiency and become dependent on capital and the global market for their earnings. How do they survive, remains a valid question. They are advised to be *atamanirbhar*, self-reliant. Moreover, when the *Adivasis* women were self-sufficient and self-reliant, they were forced to move out of their traditional life and moved to globalization where they were made to be dependent on the industrialized and unorganized sector. Now, at this stage, they are again asked to be *atmanirbhar*. Sir, the tribal people need to be protected in their own environment without being disturbed very much from the original nature. Sir, the Indira Gandhi National Tribal University in Amarkantak of Anuppur District of Madhya Pradesh was established, through an Act of Parliament under the Indira Gandhi Tribal University Act, 2007, by the Government of India. We need a tribal university in Tamil Nadu for enhancing the educational aspirations of the tribal population in the country. There are about 36 groups of tribal population in the State. Sir, in Tamil Nadu, Adi Dravidar Housing and Development Corporation Limited, TAHDCO, was incorporated in 1974, a brainchild of our visionary leader, the then Chief Minister, Dr. Kalaignar under the Companies Act, 1956. This is the first of its kind initiative in India. No other leader has shown such a love and care for the marginalized people in the country. There are very important tribal development measures taken by the Government of Tamil Nadu for imparting skill development training to tribal people. Tamil Nadu, under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, has several path-breaking schemes and training programmes exclusively for the development and improvement of the overall status of tribal population. There are several important schemes implemented for Adi Dravidars through TAHDCO. Some of them are the land purchase scheme, the land development scheme, entrepreneur development programme, EDP, special scheme under EDP Assistance for Petrol, Diesel, Gas retail outlets, self-employment programme for youth, special self-employment programme for youth, financial assistance for medical and paramedical establishments, revolving fund for self-help groups, etc. These are some of the schemes which I have named, existing in Tamil Nadu. Sir, Adi Dravidar women members of women industrial tailoring cooperative

societies need to create opportunities to strengthen their skill needs specific to trades among the youth belonging to Adi Dravidars. Several skill development training programmes are organized through empanelled institutes of Tamil Nadu Skill Development for youth and wage employment. Sir, I wish the Union Government to provide adequate financial and Constitutional support for the betterment of the tribal population in the country. Sir, I want to make a special mention about Narikurava and Gypsies. They are nowhere either into the tribal or in the notified list. I asked the Government to bring a special notification on them. Our CM, our leader, MKS, has visited the gypsies' houses and taken care of them. Sir, lastly, there is one more thing. There is a saying in Government, 'one India-one language, one India-one election, one India-one culture and one India-one food.'I think all this is not needed. It should be one India and one standard of living, and that living standard we should create for the tribal people also. I also thank our floor leaders, Tiruchi Siva Anna, for giving me an opportunity. Thank you.

SHRI VENKATARAMANA RAO MOPIDEVI (Andhra Pradesh): Sir, the YSR Congress Party appreciates the initiatives that the present Government has taken over the last several years for the welfare of tribal people. The Ministry of Tribal Affairs has started several new schemes and programmes and expanded other, including the Van Dhan Vikas Karyakaram and Eklavya Model Residential Schools. However, there are a few shortcomings which would be necessary to flag and few suggestions for the overall functioning of the Ministry. First of all, I will mention some positives and suggestions. The budget is reduced in R.E. and there is underutilization of funds. I would now like to point out two things at the outset related to the budgetary allocation of the Ministry in the last few years. It has been seen that the Ministry's budget is reduced at the Revised Estimates stage. Further, there is an underutilization of the funds that are allocated to the Ministry. If we see, for the year 2020-21, the BE allocation was Rs. 7,356 crore which was reduced to Rs. 5,472 crore. Out of this, only Rs. 5,462 crore was spent. For the year 2021-22, Rs. 7,484 crore was allocated, which were reduced to Rs. 6,126 crore at the RE stage. And till 31st January, 2022, only Rs. 3,874 crore have been spent which comes out to be around 63 per cent of the Revised Estimates. With these figures, it seems difficult that we would see a 100 per cent utilisation of allocated funds.

I would suggest that the Ministry should completely utilize the funds that have been allocated to it. Covid-19 has badly affected the economy, increased malnutrition in country and affected the quality of education as well. These issues especially affect

the tribal population of the country. In such a situation, I feel, the Ministry should increase its efforts towards the welfare of Tribal population in the country.

The Ministry's allocation has seen a significant rise this year with an allocation of Rs. 8,407 crore. I hope, we see a 100 per cent utilisation of these funds in the coming year in form of various schemes of the Ministry. On the scholarships Schemes for ST Students, the Ministry has four scholarship schemes for tribal students in the country including Pre-Matric, Post-Matric, National Fellowship and Scholarship for Higher Education and National Overseas Scholarship. I appreciate that there has been a consistent utilisation of funds allocated in such scholarship schemes. However, there are important issues with the scholarship schemes that must be flagged.

The number of beneficiaries under all the scholarship schemes have stagnated in the last few years. Such a number should have increased owing to Covid-19 and lockdown but this isn't the case. Let's just take one of the scholarship schemes. If we see the number of beneficiaries under the Post-Matric scholarship scheme, there has been no substantial increase. As per the Minister's recent reply, the number of beneficiaries was 19.67 lakh in 2018-19, which increased slightly to 20.66 lakh in 2019-20, decreased to 20.58 lakh in 2020-21 and, finally, 17.77 lakh in 2021-22. Even in other schemes, there has been no major increase in targets and the number of beneficiaries. Has the Ministry tried to study what possibly could have caused such stagnation? Further, what steps has the Ministry taken to increase allocation for scholarship scheme and the number of beneficiaries? Another issue that is most important, which has been reiterated time and again, is the income ceiling under the Scholarship Schemes. Under the pre-matric and post-matric scholarship, the parents' income ceiling was last revised in 2013. The National Overseas Scholarship also has an income eligibility criterion of Rs. 6 lakh annually. There is an urgent need to revise the ceiling limit for these scholarships. Going one step forward, I would further suggest that the Ministry should explore ways to link such income eligibility criteria with increasing inflation and explore mechanism for frequent revision of the income ceiling. Coming to Eklavya Model Residential Schools, the Eklavya Model Residential Schools were first announced back in 1997-98 to impart quality education to tribal children in their own environment in the remote areas across the country. During the 2018-19 Budget, it was announced that every block having 50 per cent or more ST population will have the Eklavya Model Residential School. The Ministry has sanctioned 28 Eklavya Model Residential Schools for the State of Andhra Pradesh. As per the information given by the Ministry, some of the schools are non-functional. I would request the Minister to review the ongoing progress, expedite the completion

of such model schools and sanction more such schools in all blocks that meet the criteria. Another thing that is important to point out here is that the Tribal Affairs Ministry proposed an allocation of Rs. 6509 crores for BE 2022-23 towards the Eklavaya schools. However, only Rs. 2000 crores have been allocated. How does the Ministry plan to cover the reduced allocations as compared to the demand? Would such a reduced allocation have any effect on completion of ongoing works and development of new schools? I would also request the Minister to relax the criteria for Eklavya schools so that such model schools could be set up in other areas as well which have substantial tribal population but don't fulfil the criteria. Coming to Van Dhan Vikas Karyakram, Van Dhan Vikas Karyakram is an initiative targetting the livelihood generation for tribals by harnessing the wealth of forest, Van Dhan. Under this programme, TRIFED sets up tribal community-owned Minor Forest Produce centric multi-purpose kendras in the districts with significant tribal population. In total, 52976 Van Dhan Self Help Groups and 3110 Van Dhan Vikas Kendras have been sanctioned across the country catering to the 927927 forest gatherers. (*Time bell rings*)

I now come to AP issues - the Central Tribal University of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 provided for setting up of a Central Tribal University in Andhra Pradesh. The Central University (Amendment) Act, 2019 was passed by the Parliament for establishment of the University. It started functioning through a transit campus from the year 2019-20. However, the University still lacks a permanent campus and necessary infrastructure. The AP CM, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy, has allocated the requisite land for setting up of the Central University and is ready to provide all support needed. I would take this opportunity to request the Government to expedite the development works related to the Central Tribal University of Andhra Pradesh. Thank you.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Respected Vice-Chairman, Sir, *Adivasi* community in our country is facing a lot of problems, but the Union Government is not ready to address the issues properly. Basically, they have failed to address the issues. The Government has declared some programmes, but nothing is happening in the field. This is the reality. Please look at the conditions of the *Adivasi* communities in India. In this august House, the Minister of Tribal Affairs had given an answer to my question that clearly shows the pathetic condition of the *Adivasi* community of our nation. The intervention of the Union Government towards tribal welfare is a failure. We are again seeing here. Interestingly, I am sharing some of the figures of fund allocation and utilisation. Sir, in 2021-22, fund allocation for model residential schools was Rs. 1200

crores, but the utilisation was zero. A lot of research could be done in the tribal sector. But, the Government is not allocating funds for research activities. Tribals have a lot of indigenous knowledge. It should be protected and preserved. Sir, out of Rs. 60 crores allocated for Tribal Research Institute, only Rs. 1.6 crores has so far been utilized in 2021-22. Utilization for the Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme is only Rs. 164 crores, which is one-fourth the price of an aircraft. The literacy rate of Advasis is only 58.95 per cent, which is lower than the general population. In every indicator, Advasis are on the back-foot when compared to the general population. The life expectancy is another indicator. Life expectancy of Adivasis is 60 years, which is lower than the life expectancy of general population. I can explain various issues one-by-one. Sir, Adivasis have higher IMR as compared to the general category people. Sir, IMR for Adivasis is 44.4, which is 40 per cent more than the general category people and 10 per cent more than the national average as per one Report. Scheduled Tribes make up 8-9 per cent of the population. But, Sir, they account for about 40 per cent of all under-5 deaths and 23 per cent of deaths in 1-4 age group in rural areas. Comprising about 8 per cent of India's population, they account for 25 per cent of population living in the poorest wealth design. Digital divide is very high in Adivasi community. According to the 75th NSSO data, 77.3 per cent of Adivasi population has no access to internet and 90 per cent of Adivasi students could not access online classes during lockdown. Sir, Adivasi areas lack good libraries and reading rooms. We are seeing these. They have lack of access as far as public spaces is concerned. In many dry regions, drinking water itself gets scarce. Most of Adivasis are working in informal sector. The ratio of formal sector employment is very low. Sir, there is an urgent need to address these issues. The allocation for development of ST is very low and even the allocated amount is not utilized. Last year Budget allocation was Rs. 7,484 crores. But, out of this allocation, only Rs. 6,126 crores was spent. In other words, the Government did not spend 19 per cent of money it allocated. This is an unfortunate situation. Sir, Advasis constitute 8.6 per cent of total population. Thus, at least, 8.6 per cent of total Budget expenditure must be allocated to STs. But, the Government has allocated just 2.26 per cent of the total expenditure for Adivasis. It has been pointed out by various hon. Members. Sir, there are a lot of issues here. I am not going to touch all those. I am only touching the allocation of funds for Adivasis. The curtailment of social security expenditure in this Budget is against the interest of Adivasis. The food subsidy has been reduced by Rs. 80,000 crores and funds for the employment guarantee schemes was reduced by 25 per cent. This will affect Advasis the most.

Sir, inflation and joblessness is rising and the Budget has no comprehensive measures to counter it and the worst sufferers will be the Adivasis.

So, we should discuss all these things and the Government should address all these issues.

Sir, Komaram Bheem, a great leader of Tribals and great fighter of exploitation, gave the slogan 'Jal, Jungle, Zameen.'

5.00 P.M.

So, I request the Government to address this issue, otherwise the struggle of *adivasis* will continue.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Thank you, Vice-Chairman, Sir, for having given me this opportunity to participate in this discussion on behalf of the AIADMK. I would like to say certain things about the grants allocated to the Ministry of Tribal Affairs for the year 2022-23.

The Ministry administers various Centrally-sponsored schemes, besides special Central assistance to tribal schemes, and grants-in-aid, under Article 275(1) of the Constitution, to contribute in the overall development of the tribal people of our country.

Sir, I have got so many lists, when I am reading this. But, at the same time, as other hon. Members asked, whatever allocations the Government is making is not being properly utilized and spent. That is my observation. For example, paragraph 2.6 gives the reasons due to which the Budget estimates were reduced in 2020-21 and 2021-22 at the revised stage; and, these revised estimates could not be spent during the period. The Ministry has submitted this reply. When the money had been allocated, why was it not spent? Please explain this to us.

Now, there is another aspect. I am very happy about it. Madam Nirmala Sitharaman has presented the present Budget. She has given an outlay of Rs. 8,451 crores for the Ministry of Tribal Affairs for the year 2022-23. This is actually an increase of 12.2 per cent. We appreciate the Government for this kind of measure.

[THE VICE CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY) *in the Chair.*]

Sir, many other schemes have been announced by the Government. Hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, is very keen to see the development of tribal people. Let me give you an example. Yesterday, we discussed the development in the North-

Eastern Region. In that area, most of the people are tribal people. We discussed the measures taken by the Modi Government to develop the area. Therefore, the Government has good intentions to see to it that the tribal people are benefitted.

In Tamil Nadu, we have two reserved Assembly constituencies for tribals. But, their population is high. It is not that the State of Tamil Nadu does not have tribal people. There are a lot of tribal people. Our the then Chief Minister, Edappadi Palaniswami, and the then Deputy Chief Minister, Paneerselvam, had written so many letters to the Central Government to include certain communities in the tribal category. For example, if you take the Badagas community in Ooty, these are only tribal people. But, they are still considered OBC. Also, there is one Valmiki community. In Karnataka, the Valmiki community falls under the Scheduled Tribe category. But, in Tamil Nadu, they are OBC. Therefore, we had represented that the Valmiki community must be included in the ST category. But, no action has yet been taken in this regard. It is my duty to highlight the problems that we are facing in Tamil Nadu. I request the hon. Minister to kindly consider these things. Secondly, tribal people live in forests; hunting is their livelihood. If you take this aspect into account, even the fishermen community should be included in that category. In Tamil Nadu, the previous Government of, Edappadi K. Palaniswami, had written a letter to include the fishermen community also in the Scheduled Tribe category. (*Time bell rings*) Sir, I have just started. This is a very important issue. Last time, the fishermen community came with a delegation to meet the Minister. I was also there at that time. But this is high time. The Tamil Nadu fishermen community is suffering a lot. They spend their life in sea for months together, leaving their families back at home. Since they are not fully educated, they are suffering a lot. So, they must be included in the category of Scheduled Tribe. It needs to be ensured that many welfare schemes are given to the fishermen community. That is my demand, Sir. Thank you very much.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे सदन के नेता प्रो. राम गोपाल यादव जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे जनजातीय कार्य मंत्रालय की 2022-23 की अनुदान माँगों पर हो रही चर्चा में बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी जो आदिवासी हैं, जनजाति के लोग हैं, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जबकि सरकारें तमाम बजट भेजती हैं और केन्द्र सरकार ने उनके लिए बजट फिक्स किया हुआ है। जल और जंगल पर आदिकाल से आदिवासी जनजातियों का आधिपत्य रहा है और जब से सृष्टि की रचना हुई है, भारत के मूल निवासी द्रविड़ और आदिवासी जनजातियाँ थीं, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद या उससे पहले जब अंग्रेज़ थे, तब भी उनका विकास नहीं हुआ। वन संपदा में उनका जो अधिकार था, वह सारा छीना जा रहा है।

आज हम देख रहे हैं कि एसटी आबादी वाले लगभग 1,17,000 गाँव हैं, लेकिन आज वहाँ स्कूल्स नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, तमाम जगहों पर बिजली नहीं है, टेलीफोन सुविधा नहीं है। मानव के विकास के लिए जो तमाम मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, आज वे भी नहीं हैं।

मान्यवर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में उन्हें साढ़े सात परसेंट आरक्षण दिया था, लेकिन आज भी उनका आरक्षण पूरा नहीं है। देश में उनके 1.1 परसेंट आईएएस अधिकारी भी नहीं हैं, कोई कुलपति नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है और जब विदेश में कोई ट्रेनिंग होती है, वहाँ उनका एक भी अधिकारी नहीं भेजा जाता है और यह कह दिया जाता है कि सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। मान्यवर, हमारे जितने भी आदिवासी हैं, देश की आज़ादी में उनका बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उस समय सड़कें नहीं थीं, पुल नहीं थे। हमारे बिरसा मुंडा जी और तमाम आदिवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया था, लेकिन आज वही लोग मूल सुविधाओं से वंचित हैं।

हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज देश में रोजगार की कमी है। कोई एसटी का व्यक्ति है, जैसे मध्य प्रदेश में कोई मांझी समुदाय का व्यक्ति है, अगर वह दिल्ली चला जाता है या किसी और स्टेट में चला जाता है, तो वहाँ वह सामान्य कैटेगरी में आ जाता है। इसे लेकर हम लोग संकल्प भी लाए थे, बिल भी लाए थे और हम लोगों ने इनके डेवलपमेंट की माँग की थी। जब उनका रोजगार कहीं और चला जाता है, तब उन्हें आरक्षण से भी वंचित कर दिया जाता है। इसके साथ ही, वन संपदा में भी इनका अधिकार छीना गया है।

मान्यवर, वहाँ जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें दोहरी शिक्षा नीति है। उस शिक्षा से कोई आईएएस नहीं बन सकता है। अगर पेपर होता है, तो एक ही होता है। अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उसे qualify करेगा, तो दोहरे पेपर की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए इस दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करके सामान्य शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए।

हम देख रहे हैं कि देश में जो तमाम घुमक्कड़ आदिवासी जातियाँ हैं, आज उनकी कोई गणना नहीं है। हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जाए, उनकी गिनती कर ली जाए। उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी दी जानी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' हैं, वे एसटी बहुल एरियाज़ में नहीं हैं, बल्कि सामान्य एरियाज़ में हैं। नाम तो उनके हैं, लेकिन उनको वंचित किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि उनसे उनकी शिक्षा के अधिकार को छीना जा रहा है, क्योंकि पढ़ा-लिखा व्यक्ति सवाल करेगा और अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा? आज उनको केवल पाँच किलो चावल और एक किलो नमक पर जीने के लिए छोड़ दिया गया है। ...**(समय की घंटी)**...

आज एससी, एसटी के लोगों का भरोसा उठ गया है कि ईवीएम में मोबाइल की तरह सॉफ्टवेयर है। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, तब तक जनता का जनादेश नहीं आएगा। इनके आरक्षण का कोटा नहीं है। पूरे देश में प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है। इससे नौकरियों में इनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम सभी राजनीतिक दलों से यह माँग करेंगे कि वे ईवीएम का बहिष्कार करें, बैलेट पेपर से उचित चुनाव कराएँ। जिन लोगों ने ईवीएम मशीन बनाई, वे लोग बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, तो आज उनके जनादेश का सम्मान होना चाहिए। हमने यूपी में देखा कि अखिलेश यादव जी को 304 सीटों पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से बहुमत मिला और इस

तरह से उनको 51.5 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन वहाँ पर उनको सरकारी मशीनरी तथा ईवीएम से हरवा दिया गया।

मान्यवर, मैं यही कहूँगा कि जो आदिवासी वनवासी हैं, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट दिया जाना चाहिए। **...(व्यवधान)...** ***...(व्यवधान)..** * **...(व्यवधान)...** * हुआ है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : कृपया अब आप समाप्त कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : पंचायतों के अंदर **...(व्यवधान)...** * **...(व्यवधान)...**

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार)**:** वाइस चेयरमैन सर, मैंने कल से एक कोशिश शुरू की है, इसलिए आज मैं अपनी बात की शुरुआत तमिल की एक लाइन से करना चाहता हूँ। उसके उच्चारण के लिए मैं पहले ही माफी माँग लेता हूँ। *Pazhangudinar kurittu pesa anumadi thanndatharkku nandri thunaithalaivar avargale.* इसका मतलब यह है कि मैं आज आपकी अनुमति से इस विषय पर, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, बीएसी की मीटिंग में आप भी थे। उसमें यह चर्चा हुई थी कि जब इन विषयों पर विमर्श होगा, तो थोड़ा लिबरल रहा जाएगा। हम सदन में साल भर में ट्राइबल डेवलपमेंट पर आम तौर पर चर्चा नहीं करते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर एक-दो मिनट ऊपर-नीचे हो जाएं, तो उसके लिए मैं पहले ही माफी माँग लेता हूँ।

वाइस चेयरमैन सर, मैं अपने सुझाव और अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराने से पूर्व आज इस सदन में जयपाल सिंह मुंडा को याद करना चाहता हूँ। सर, पीछे सेंट्रल हॉल है और जब कॉन्स्टिटुएंट असेम्बली की बहस हुई थी, तो जयपाल सिंह मुंडा साहब ने जिन विषयों को उकेरित किया था, जिनको सामने रखा था, हम आज भी उनसे मीलों दूर हैं। माननीय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आप मुझसे इत्तेफाक रखेंगे, भले ही हमारे दल अलग-अलग हों, लेकिन हमारे दिल उस मामले में जुड़े हुए हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले एकलव्य मॉडल स्कूल पर आता हूँ। एकलव्य मॉडल स्कूल में 'एकलव्य' बोलते ही हमारे ध्यान में अंगूठा आता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा माँग लिया था। सर, अब के जो द्रोणाचार्य हैं, वे हाथ ही काट लेते हैं। वे मस्तिष्क को हाइजैक कर लेते हैं। मैं तो कहूँगा कि इस नाम पर दोबारा विचार हो, कुछ और सोचा जाए, क्योंकि एकलव्य मॉडल स्कूल के माध्यम से हमने बिना व्यवस्था के, बिना गुणवत्ता के यह तय कर लिया है। एकलव्य तो कम से कम दूर से देखकर तीर-धनुष चलाना सीख गया था, लेकिन आज के एकलव्य को हम ऐसी परिस्थिति में पहुँचा रहे हैं, जहाँ वह बाजार में खड़ा होगा, लेकिन उसकी लेबर का, उसकी expertise का, उसकी skill का कोई खरीदार नहीं होगा। तो, हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई, बजटरी एलोकेशन हो गया! माननीय मिनिस्टर साहब, मैं तो

---

* Expunged as ordered by the Chair.

यह कहूँ कि बिहार में sanction-one zero है। अगर मैं आपको अलग-अलग राज्यों का आँकड़ा दूँ, तो जम्मू-कश्मीर में छः सैंक्शन, ज़ीरो ऑपरेशनल है। इस तरह से, ऐसे कई राज्य हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक विश्वविद्यालय से आता हूँ। सर, जैसा मैंने कहा, अगर आप हायर एजुकेशन में देखें, तो पता चलेगा कि वंचित और बहुजन समाज के लोगों का ऊपर तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है। सर, हर मोड़ पर अवरोधक लगे हुए हैं और वे अवरोधक दिखते नहीं हैं। सड़क पर तो यह दिखता है कि आपने स्पीड ब्रेकर लगा दिया। Similarly, there are breakers everywhere, and those breakers have ensured that the representation is either zero or very paltry. सर, यह बात मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। 'Suitable', 'Not Found Suitable', अभी हाल में हमने इस पर चर्चा की है। सर, कुछ बिंदुवार बातें करते हैं। कल नॉर्थ-ईस्ट रीजन की बात हो रही थी, तो मैंने जवाहरलाल नेहरू जी का ज़िक्र किया था कि tribal के लिए जो पंचशील का सिद्धांत था, उसमें एक difference उन्होंने बार-बार की थी। वह बड़ी लम्बी डिबेट थी, संभवतः उनकी और एक anthropologist की डिबेट थी। उन्होंने कहा कि inclusion के लिए जाओ, intrusion के लिए न जाओ। अधिकांश आदिवासी इलाकों में, चाहे इनकी सरकार रही हो या आपकी सरकार हो, आपने inclusion को intrusion का रूप देने की कोशिश की है। मैं बार-बार कहूंगा कि जब आप कुछ इलाकों में नक्सलवाद की समस्या देखते हैं, वह law and order की problem नहीं है, that is also a problem of our social order. मैं अभी भी दोहराऊंगा कि you have to fight this extremist ideology by infusion of development with an agenda of inclusion, not intrusion. मैं यह आपके सामने रखना चाहूंगा।

सर, displacement को लेकर भी हम अक्सर रटी-रटाई बातों में जाते हैं। खासकर जो vulnerable tribal groups हैं, उनकी ओर तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। अब मैं एक आंकड़ा लेता हूं। सर, 41 प्रतिशत tribal population illiterate है और 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक 6.7 परसेंट लोग ही ऐसे हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। क्या यह सामूहिक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, न सिर्फ इस मंत्रलाय के लिए, न सिर्फ इस संसद के लिए, बल्कि हमारे सामाजिक सरोकार के लिए?

सर, हम हैल्थ की बात पर आते हैं, तो triple burden है। पहला burden है, malnutrition. अभी मंत्री महोदया यहां मौजूद थीं। दूसरा है - rapid urbanization without any logic. Third, and one that is very, very important, is because of the lifestyle change and rapid urbanization, the third burden is of non-communicable diseases. अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला के साथ जो हुआ, उसके बारे में हम सब जानते हैं। यह सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ है। ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं एक-डेढ़ मिनट और लूंगा। यह सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ, बल्कि आए दिन हम ऐसी खबरों को देखते हैं, तात्कालिक चिंता व्यक्त करते हैं और फिर अपनी ज़िन्दगी में आगे निकल जाते हैं। मैं आपके through कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, Pre-Matric Scholarship Scheme का आप स्वयं ब्यौरा ले लीजिए। आपको चिंता होगी, इतनी चिंता होगी कि आप सोचेंगे कि फिर से झारखंड की राजनीति में सक्रिय हुआ जाए! मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि वह allocation stagnant है, आप Revised Estimate देख लीजिए। Post-Matric Scholarship Scheme की वही हालत है।

सर, मैंने अभी हाल में माननीय शिक्षा मंत्री जी को लिखा और माननीय प्रधान मंत्री जी को भी लिखा। एक स्कॉलरशिप है - National Overseas Scholarship. इसमें एक ऐसी तब्दीली की गई है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे! खासकर यह स्कॉलरशिप वंचित समुदाय के लोगों के लिए थी। अब कोई भी Indian student Indian Heritage, History, Culture, Societal Concerns पर विदेश में रिसर्च नहीं कर पाएगा। आज बाबा साहेब अम्बेडकर होते तो क्या कहते! कोलम्बिया की उनकी स्टडी का क्या होता! And a large number of people who have used the mechanism of higher education in the West, वे treasure हैं, उनकी manuscripts हैं। आप ऐसे कैसे विश्व गुरु बनेंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): ठीक है।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, विश्व गुरु वाली बात भी आ गई है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): You have already exhausted the time.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा। Reports of the Commission since 2018, यह भी चिंता का विषय होना चाहिए। वह आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, सदन में आयी ही नहीं है। वर्ष 2018 से आज तक नहीं आयी है। क्या यह पारदर्शिता है, क्या यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? Empty rhetoric doesn't help. आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज मान्यवर कांशीराम से संबंधित यह दिन है। मैंने जयपाल सिंह मुंडा से शुरुआत की है। मान्यवर कांशीराम जी को माला पहनाने और सिर झुकाने से आगे बढ़कर आप उनके विचारों को आत्मसात कीजिए। जोहार-जोहार, जय-हिन्द!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Shri Binoy Viswam; not present. Shri Ram Nath Thakur.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो विधेयक आया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। सर, 75 वर्ष हो गए हैं। हमारे पूर्वजों ने इन समाजों के लिए जो उम्मीदें और विचार रखे थे, उस समाज का उत्थान, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति कितनी हुई है, इस पर हमें सोचना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि 136 करोड़ की जनता में 11 परसेंट इन जातियों का समावेश है। हमने इन 11 परसेंट जातियों के लिए क्या किया? उनमें से कितने डॉक्टर्स बनाए, कितने इंजीनियर्स बनाए, कितने प्रोफेसर बनाए, कितने शिक्षक बनाए, कितने आई.ए.एस और आई.पी.एस. बनाए, इस पर हमें सोचना चाहिए। इन जातियों के लिए जो उसका जल-जंगल-ज़मीन है, उनके साथ, उनके बीच में, उनके गांव में, उनके टोलों में नक्सलवादी क्यों पनप रहे हैं, वे वहां क्यों जा रहे हैं, उनको बाधित क्यों कर रहे हैं, उनको आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इस पर हमें सोचना और विचार करना चाहिए और इसका उपाय भी खोजना चाहिए। तीसरा, अभी

आदिवासियों के नाम पर, जनजातियों के नाम पर जो योजनाएं हैं - जैसे पेट्रोल पम्प आदिवासी के नाम पर है, लेकिन उसका मालिकाना हक किसका है, उसका नाम तो है, लेकिन उसका हक किसको है, इस पर हमें सोचना और विचार करना चाहिए और इस सरकार को यह करना चाहिए कि यदि आदिवासी का नाम है, जनजाति का नाम है, लेकिन मालिकाना हक दूसरे का है, तो इस पर आधिकारिक तौर पर आदिवासी को, जनजाति को अधिकार दिलाना चाहिए, यह मेरा सजेशन है।

चौथी बात यह है कि शिक्षा में उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, वे 75 वर्षों में कितने परसेंट शिक्षा के मामले में आगे बढ़े हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। सर, 12 राज्यों में इन जातियों की संख्या का बाहुल्य है। इन 12 राज्यों में जितनी संख्या है, क्या सरकार उसके आधार पर उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करेगी?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा पांचवां और अंतिम प्वाइंट यह है कि आइए, हम सब मिलकर यह देखें कि 75 वर्षों में हमने उन लोगों के लिए जो काम नहीं किया, जो योजनाएं दीं, जो पैसे दिए, लेकिन उनका सही उपयोग नहीं कर पाए, तो क्या हम इस वित्तीय वर्ष में उनकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर पाएंगे? महोदय, अब मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं।

'चमन के सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी,
यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का,
चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से,
वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का।'

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत!

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश)**:** धन्यवाद माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय। नर्मदे हर! मुझे जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यकरण की चर्चा पर सहभागिता का अवसर प्रदान किया गया है। मैं मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र से आता हूं और आज मुझे किसी विषय पर पहली बार बोलने का अवसर मिला है। डेढ़ साल से इंतजार करते-करते ये दिन आ गए, पर विपक्ष ने कभी सदन को ठीक से नहीं चलने दिया। मुझे आज मौका दिया गया है, मैं आपका फिर से आभार प्रकट करता हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मेरी maiden speech भी है। जनजातीय समाज अब निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और देश में सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी जनजातीय समाज को लगातार मिल रहा है। आजादी के बाद पहली बार शिक्षा, चिकित्सा, रोज़गार और प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे रही है और मैं इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान देने के साथ-साथ गरीबों, दलितों, आदिवासियों की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी लगातार

जनजातियों के विकास को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने किसी भी जनजातीय महापुरुष को इस प्रकार का सम्मान नहीं दिया, जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने दिया है। इसी कड़ी में पिछले वर्ष 15 नवम्बर, 2021 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का जो कार्य किया है, मैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय नरेन्द्र मोदी जी का और पूरी सरकार के सम्माननीय सदस्यों का देश के 12 करोड़ जनजातीय भाइयों और बहनों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आजादी से अब तक जनजातीय महापुरुषों को कभी भी इतिहास के पन्नों पर ठीक से जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस देश के सर्व-सुसज्जित हाईटेक रेलवे स्टेशन का नाम भोपाल में रानी कमलापति के नाम से रखा गया और अन्य स्थानों के नाम भी लगातार जनजातीय महापुरुषों के नाम पर रखे जा रहे हैं। यह जनजातीय समाज के लिए गौरव और सम्मान का विषय है और मैं देश के प्रधान मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्य सभा सांसद हूं। बकरी चराते-चराते, स्कूल में शिक्षक होने के बाद यहां आकर मेरे 12 करोड़ जनजातीय भाइयों और बहनों के लिए बोलने का अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया है। मैं इसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त करूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करूंगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 8,451 करोड़ रुपये की बजट परिव्यय में 12.32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। हमारे विपक्षी साथी बोल रहे थे कि यह बहुत कम वृद्धि है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस वृद्धि के पहले अगर अपने 60 सालों तक काम किया होता, तो हमारे लिए कोई काम बचता ही नहीं और इस वृद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप लोगों ने 60 सालों तक हमको तरसा कर रखा। इन्होंने जनजातीय समाज को वोट बैंक समझ कर रखा और मैं उसी विषय को यहां पर रखना चाहता हूं। कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग चक्र में जनजातीय विकास के लिए 58,399 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एसटीसी घटक में 87,500 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए खाका पेश करने का प्रयास किया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत काल अब जनजातीय समाज के लिए स्वर्ण काल साबित होगा। सामुदायिक चेतना के साथ, सामूहिक विकास और सामूहिक सम्मान का आगाज़ देश में हो चुका है और अब जनजातीय समाज पूरे स्वाभिमान के साथ और आत्म-सम्मान के साथ जीने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कभी भी जनजातीय समाज के महापुरुषों का स्मारक बनाने के लिए एक ईंट भी खरीदकर नहीं रखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश के अंदर महापुरुषों के स्मारकों को बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया है, इसलिए यह हमारे समाज को गौरवान्वित करने वाला विषय है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि जनजातीय महापुरुषों के नाम पर रेलवे स्टेशन और

एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया है। जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को लिखने की दिशा में भी काम किया जा रहा है और उसके संरक्षण का काम भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार कर रही है। अब जनजातीय समाज के भाई और बहनों को इतिहास में उचित स्थान मिलने की पूरी संभावना है और इसके लिए पूरा जनजातीय समाज आशान्वित है। आपने पिछले चुनावों के परिणामों में यह देख भी लिया है कि चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतकर आई है, क्योंकि जनजातीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जनजातीय समाज की संस्कृति, परम्परा, रीति-रिवाज के संरक्षण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। पहले हमारे क्षेत्र के अंदर जनजातीय समाज की संस्कृति और परम्परा को मिटाने का काम किया जाता था, लेकिन 60 साल की कांग्रेस सरकार ने कभी भी हमारी संस्कृति और परम्परा को बचाने का काम नहीं किया। यह भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की सरकार है, जो माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जनजातीय लोगों की संस्कृति और परम्परा को संरक्षित करने का काम भी कर रही है।

हमारे जनजातीय समाज के लिए अलग जनजातीय आयोग का गठन किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय को अलग से बनाया गया और आज जनजातीय कार्य मंत्रालय पूरे देश के 12 करोड़ दलित, शोषित और पीड़ित जनजातीय भाई और बहनों के लिए काम कर रहा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा जंगलों से गहरा रिश्ता है। जल, जंगल और ज़मीन की बात विपक्ष हमेशा से करता रहा है। वामपंथी पार्टियों के साथियों ने भी हमेशा जल, जंगल और ज़मीन की बात कही है, परन्तु उनका जल, जंगल और ज़मीन से कोई रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने पिछले 60 सालों में जल, जंगल और ज़मीन में जाकर कभी झांका तक नहीं है। आज जल, जंगल और ज़मीन में रहने वाला एक किसान का बेटा यहां सदन में आकर इस विषय को रख रहा है और मैं वास्तविक विषय पर ही अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा। मैं कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथियों से कहना चाहता हूं कि जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों पर आपने हमेशा राजनीति की है, आपने हमेशा उनको राजनीतिक मुद्दे बनाकर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने का प्रयास किया है। आपने जनजातीय भाई और बहनों को जल, जंगल और ज़मीन के लिए आपस में लड़वाने का काम भी किया है। आपने जनता के बीच में, जनजातीय भाई और बहनों के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम भी किया है, उनके बीच संघर्ष खड़ा करने का भी प्रयास किया है। मैं अपने सभी विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूं कि अब जनजातीय समाज जाग चुका है और अब वह इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होने देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी संरक्षक बनकर खड़ी है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जल, जंगल और ज़मीन के कामों को धरातल पर उतारने का काम किया है। अभी हमारे एक विपक्षी साथी जनजातीय लोगों को पट्टा देने की बात कह रहे थे, वनाधिकारों की बात कह रहे थे। मैं पूरे दावे के साथ बताना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था, बकरी चराता था, तब मेरे पिताजी को वनाधिकार का पट्टा दिया गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और आज हज़ारों लोगों को वनाधिकार के पट्टे दिये गये हैं। मैं इसके लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का और केन्द्र की सरकार का आभार

व्यक्त करना चाहता हूं । अगर हम जंगल की बात करें, तो वन धन केन्द्रों को स्थापित करने की दिशा में भी सतत प्रयास किया जा रहा है। जब वन धन केन्द्र स्थापित हो जायेंगे, तब मुझे लगता है कि जनजातीय समाज को वन-धन केन्द्रों के माध्यम से वन में जो उत्पादन हो रहा है, उसका उचित मूल्य मिलना शुरू हो जायेगा, इसलिए जंगल का जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केन्द्र की सरकार ने 'वन बंधु कल्याण योजना' शुरू की है। मैं जिस जिले में रहता हूं, उसमें तो यह योजना है ही, जिसके कारण हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों में 'वन बंधु कल्याण योजना' प्रारम्भ की गई है। हमारे जिले को आकांक्षी जिला भी घोषित किया गया है। देश में ऐसे सैकड़ों जिले हैं, जिन्हें आकांक्षी जिले घोषित करके उनके विकास की दिशा में काम किया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं वनाधिकार पट्टों की बात करता हूं। साठ साल पहले, जब कभी विपक्ष की सरकार थी, तब हमारे जनजातीय भाई और बहनों को जंगल के अंदर से खदेड़ दिया जाता था। वे पंद्रह-पंद्रह, सोलह-सोलह, बीस-बीस सालों तक खेती करते थे, लेकिन वनाधिकार का पट्टा तो दूर की बात है, उनको वहाँ ठीक से खड़े भी नहीं रहने दिया जाता था। उस समय ये हालात थे, लेकिन आज ये हालात ठीक हो गए हैं। मैं कहता हूं कि पूरा जनजातीय समाज, पूरे आत्मसम्मान के साथ अब पट्टे प्राप्त करके उसमें प्रधान मंत्री आवास भी बना रहा है, कुएं खोदकर पानी देने का काम भी किया जा रहा है, उनको बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है और वन-धन केंद्रों के माध्यम से महंगे दामों पर वनोपज बेचने के लिए भी उनको प्रेरित किया जा रहा है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय का एक अद्भुत काम है, जो इस देश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।

महोदय, प्रसिद्ध लेखक और चिंतक रामदयाल मुंडा ने कहा था कि कांग्रेस की सरकारें ट्राइबल्स सब-प्लान के नाम पर बड़ी-बड़ी राशियाँ तो आवंटित करती थीं, लेकिन जनजातीय गरीब समाज जहाँ था, वहीं का वहीं रह गया। यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ हमें एक चॉकलेट बाँधकर दे दी थी, जो लटका दी गई थी, लेकिन बच्चे के हाथ में चॉकलेट नहीं दी थी। विपक्षी पार्टियों ने वही हाल हमारे जनजातीय समाज के साथ साठ सालों तक किया है। You are pointing out at the money-leakage system. माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस लीकेज को समाप्त कर दिया है। हमारी सरकार अब जनजातीय भाइयों और बहनों को, गरीबों और दलितों को उनका संपूर्ण अधिकार और पूर्ण राशि दे रही है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

महोदय, हमारे विपक्षी साथी बोल रहे थे कि यह नहीं किया, वह नहीं किया। वे इस तरह से गिनवा रहे थे कि सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं मिली, इतने गाँवों में प्रधान मंत्री आवास नहीं बने, इतने गाँवों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है आदि-आदि। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप साठ सालों तक यह काम करते, तो आज आपको इनको गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और हम आपको उनके इतने काम गिना देंगे कि आप उन्हें गिनते-गिनते थक जाएंगे। आपने साठ सालों तक काम नहीं किया, लेकिन सात सालों के कार्यकाल की तुलना करने बैठ गए हैं! मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आपने जनजातीय समाज को वोट बैंक समझने की भूल की है और आप उसके परिणाम भी भुगत रहे हैं।

महोदय, हमारी सरकार ने पद्म भूषण जैसे श्रेष्ठ सम्मान भी जनजातीय समाज के भाइयों और बहनों को देने का काम शुरू किया है। मैं उसके लिए भी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बचपन में झोंपड़ी में जाकर फोटो खिंचवाने की फोटो देखा करता था। कांगेस के बड़े-बड़े नेता थे, वे झोंपड़ी में जाते थे, खाना खाते थे और फोटो खिंचवाया करते थे, पर उन्होंने कभी भी उस झोंपड़ी को महल बनाने का प्रयास नहीं किया। देश के प्रधान मंत्री ने आज करोड़ों जनजातीय भाइयों और बहनों को प्रधान मंत्री आवास बनाकर दिया है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। मैं आपको मेरे बचपन की एक घटना बता रहा हूं कि एक बार जब बारिश हो रही थी, तो हमारा घर टपक रहा था, छत चू रही थी, आँसू आ रहे थे। मेरे पिताजी ने कहा कि, 'बेटा, रात भर इधर-उधर खटिया सरका लो, बारिश कम हो जाएगी, थोड़ा-सा बच जाएंगे, तो मैं सुबह कवेलू ठीक कर दूंगा।' वे खटिया सरकाते रहे, पर बारिश तो पूरे घर में चू रही थी, इसलिए पूरा घर गीला हो गया। हम परेशान होते रहे, पिताजी चिमनी जलाकर देखते रहे, लेकिन वह फिर भी ठीक नहीं हुआ। यह बात जब देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने आज देश में करोड़ों जनजातीय भाइयों और बहनों को प्रधान मंत्री आवास बनाकर दिया है और अब हमें रात में खटिया सरकाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जो भाई-बहन हैं, वे कहते हैं कि हमारे पिताजी या हमारे भाई ने तो इतना बड़ा मकान बनाकर नहीं दिया, लेकिन देश के प्रधान मंत्री जी ने वह मकान बनाकर दिया है, जिसमें हमारी आने वाली दो-तीन पीढ़ियाँ बिना खटिया सरकाए, बिना पानी टपके, बिना भीगे, बिना गीले हुए या बिना परेशानी के रह सकती हैं। महोदय, उन्होंने उसमें 'उज्ज्वला योजना' का चूल्हा भी दिया, शौचालय भी बनाकर दिया, बिजली का कनेक्शन भी लगाकर दिया, खेतों में पानी की व्यवस्था भी करके दी और साथ में अन्य व्यवस्थाएं करने का भी लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही 'किसान सम्मान निधि' देने का काम भी किया जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो झोंपड़ी के सामने फोटो खिंचाते थे, कि अब उन झोंपड़ियों को ही हटाने की दिशा में हमारे देश के प्रधान मंत्री जी काम कर रहे हैं, इसलिए आपको झोंपड़ी के सामने फोटो खिंचवाने की जगह नहीं मिल पाएगी।

महोदय, प्रधान मंत्री आवास के बाद 'जल जीवन मिशन' और एकलव्य स्कूलों की सौगात भी दी गई है। जब मैं पढ़ता था, तो कवेलू वाले स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आज मेरे जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सैकड़ों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पर हमारे यहाँ के माननीय सांसद बोल रहे थे। उन्होंने एकलव्य जी के अंगूठे की बात कही थी, उसके बाद हाथ काटने की बात कही थी, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे लिए एकलव्य पूजनीय हैं, अतः हाथ काटने जैसा उपहास करके आपने एकलव्य के बारे में ठीक नहीं बोला है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सदन से वे माफी मांगें। 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' और 'आयुष्मान योजना' में पांच लाख रुपये की बात कही गई है। मैं बताता हूं कि हमारे देश के गरीबों को 100 रुपये इलाज करने के लिए नहीं मिलते थे, लेकिन देश के प्रधान मंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक शानदार 'आयुष्मान भारत योजना' बनाई। हमारे जनजातीय भाई-बन्धु जब इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे देश का प्रधान मंत्री सचमुच में हमारे लिए भगवान है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि यह उन गरीबों के लिए पांच लाख रुपये के नोट या चेक के समान है। इसके लिए भी मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : कृपया समाप्त कीजिए।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार ही बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : आपको टाइम मिल गया है। आपको मेडन स्पीच का टाइम मिल चुका है।

डा. सुमेर सिंह सोलंकी : पहले विदेशों में जनजातीय छात्र नहीं जा सकते थे, लेकिन अब मैं विदेशों में छात्रवृत्ति की बात करना चाहता हूं। पहले हम लोग जिले के अन्दर पैदल चलकर आते थे, क्योंकि वहां सड़क नहीं थी। हम कीचड़ में चलते थे, पानी की पिचकारियां, कीचड़ की पिचकारियां हमारे ऊपर उड़ती थीं और हमारे कपड़े खराब हो जाते थे, कई बार हमारी किताबें भी गीली हो जाती थीं। देश में आज 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' में सड़कों का जाल बिछ गया है। आज जनजाति समाज का हर बन्धु कहता है कि देश के पूर्व प्रधान मंत्री, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम आज भी याद करते हैं और घर-घर में उनकी फोटो लगाते हैं। मैं यह भी कहता हूं कि पहले हम लोग स्कूलों में पढ़ने जाते थे तो हम कभी भी जिला मुख्यालय के स्कूलों में पढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना लाकर विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था भी कर दी है और लाखों-करोड़ों रुपये अब विदेशों में पढ़ने वाले जनजातीय छात्रों को देने का कार्य किया जा रहा है। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जनजातीय बच्चों का विदेश में पढ़ने का सपना पूरा किया है। इसके सहित 'प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन' भी शुरू किया गया है और उसके अन्तर्गत जनजातीय भाइयों और बहनों का विकास किया जा रहा है। उसके सहित करीब 265 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब जनजातीय समाज का विकास होगा और होकर रहेगा।

मैं, अंत में, एक बात और कहना चाहता हूं। सारे विकास के कार्य निरन्तर चल रहे हैं, लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय रेल मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र रेल और मेडिकल कॉलेज की सौगातों से काफी दूर है। मैं यह आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ये सुविधाएं भी मिल जाएंगी तो जनजातीय समाज को एक बड़ा लाभ हो जायेगा।

मैं, अंत, में यही बात अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि विपक्षियों,

"आप जैसे कच्चे वादे हम नहीं करते,
रेत पर नाम हम लिखते नहीं,
क्योंकि रेत पर नाम टिकते नहीं,
पत्थर दिल हैं यारों हम तो,
क्योंकि पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं।"

इसीलिए तो मोदी सरकार कहती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' होगा और आपका भी साथ होगा तो-

"भारत देश में चारों तरफ खुशहाली होगी,
मुस्कानों से भरा पल होगा,
दीप जलेंगे आशाओं के,
आज से भी सुन्दर कल होगा।"

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय-हिंद, जय-भारत!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): It was your maiden speech, but you spoke like a veteran. Shrimati Phulo Devi Netam.

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज आदिवासी कार्य मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा करने के लिए मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया है। मैं सुन रही थी, सामने से कुछ बातें आ रही थीं। मुझे लगता है कि यह सरकार आदिवासियों के प्रति, आदिवासी समुदाय के प्रति संवेदनशील नहीं है।

मैं राजनीतिक भाषण नहीं दूंगी। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं उन्हीं को बताना चाहूंगी। यह सरकार का नौवां बजट है। पिछले आठ सालों में कई बजट पेश हुए, जिनको नाम दिया गया, 2015-16 का 'सब का बजट', 'विकास का बजट', 'बेहतर
भारत का बजट', 'नये भारत का बजट', 'जन-जन का बजट' और पिछले साल का बजट 'आत्मनिर्भर बजट'। मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि क्या सुंदर शब्दों वाले ये बजट देश के सबसे पिछले आदिवासी समुदायों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे? अनुसूचित जनजाति के 35.65 प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं और मजदूरी पर निर्भर हैं। क्या इनका भला हो पाया? अनुसूचित जनजाति के 74.1 प्रतिशत लोग बेहद गरीब हैं। क्या ये गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए? 2011 की जनगणना के अनुसार 86.53 प्रतिशत आदिवासियों की आमदनी 5 हजार रुपए से कम थी। अगर आज गणना की जाए, तो इनमें से अधिकांश तो 5 हजार की नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 89,265.12 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और उसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय को मात्र 8,451.92 करोड़ रुपए, यानी 9.46 प्रतिशत आवंटित हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि आदिवासियों को जो बजट मिला, उसका 10 प्रतिशत भी सीधे तौर पर उनके लिए बनी योजनाओं में नहीं मिला। बाकी 90 प्रतिशत बजट ऐसी योजनाओं में दिया जा रहा है, जो सब लोगों के लिए बनी हैं। अभी 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि' की बात की जा रही थी। भारत में सभी जातियों के लोग किसानी करते हैं, लेकिन इस स्कीम में अनुसूचित जनजाति डेवलपमेंट प्लान के 5,876 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पानी की पाइपलाइन बिछती है, तो सबके लिए; सड़क बनती है, तो

सबके लिए; राशन बँटता है, तो सभी गरीबों के लिए, लेकिन इन सब योजनाओं में अनुसूचित जनजाति डेवलपमेंट प्लान का भी पैसा डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आदिवासी मंत्रालय अलग बनाया गया, कांग्रेस की सरकार में इसके लिए अलग से बजट हुआ करता था, लेकिन आप लोग आदिवासियों के इस हक को छीन रहे हैं। जब पैसा आदिवासियों के नाम का है, तो उसे सबमें क्यों बाँटा जा रहा है? आदिवासी समुदायों के विकास के लिए लक्षित योजनाओं में ही यह धनराशि खर्च होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी वाहवाही कर रही है कि हमने आदिवासियों को 927 करोड़ रुपए बढ़ा कर बजट दिया, लेकिन अगर हम आँकड़ों को देखें, तो पता लगेगा कि पिछले बजट को संशोधित करके 1,343.57 करोड़ की कटौती कर दी गई थी। यही हाल इस बजट का भी हो जाएगा। 2021-22 में इस मंत्रालय का संशोधित बजट 6,181.30 करोड़ कर दिया गया, यानी इसमें कुल 1,343.57 करोड़ की कटौती की गई है । बजट में कटौती ऐसे समय की गई, जब पूरा देश कोरोना से पीड़ित था। कोरोना का सबसे बड़ा प्रभाव तो गरीब आदिवासियों पर भी था। आपने जो दिया, उसे दूसरे हाथ से वापस ले लिया। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासियों का हक मारा जाता है और सरकार अपनी वाहवाही लूटने में लगी रहती है। आदिवासी कार्य मंत्रालय बजट बढ़ाने की बात तो कहता है, लेकिन वह कोई नई योजना लेकर नहीं आया, बल्कि कई योजनाओं में तो कटौती कर दी गई है। हमारे साथी अभी कह रहे थे कि TRIFED को 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय' के लिए कुछ नहीं दिया गया है। राज्य सरकारों के सहायता अनुदान में 59 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इस योजना की कटौती का सबसे ज्यादा नुकसान हमारे आदिवासी राज्यों को ही होगा, खास तौर पर छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे आदिवासी राज्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

महोदय, आदिवासी समुदायों व अन्य समुदायों के 'मानव विकास सूचकांक' के बीच में बड़ा अंतर है। आदिवासी समुदायों के लिए आबादी के हिसाब से बजट आवंटित नहीं किया जाता है, साथ ही आदिवासी समुदायों के विकास के लिए लक्षित योजनाओं के लिए बजट भी जारी नहीं किया जाता है।

महोदय, पिछले वर्ष 2021-22 में जनजातीय कार्य मंत्रालय को 18 महत्वपूर्ण योजनाओं में कुल 7,484.07 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन अब तक मात्र 4,649.09 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि लगभग 37 प्रतिशत रुपये दिए ही नहीं गए, इतनी कटौती कर दी गई। ये आंकड़े मैंने मंत्रालय की वेबसाइट से ही लिए हैं, अपने मन से इसमें कुछ नहीं जोड़ा है।

महोदय, अगर मैं बोलना चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकती हूं, लेकिन सरकार से मैं एक बात कहना चाहूंगी। पिछले साल दिसम्बर में जब बजट की तैयारी चल रही थी, तब मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदया को एक पत्र लिखा था, जिसमें कुछ सुझाव भी दिए थे। आज सदन में मैं आदिवासी क्षेत्रों के लिए पुनः उन चीज़ों की मांग करना चाहती हूं। पहला, देश की आबादी में 8.6 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले आदिवासी समुदाय के लिए आवंटित किया जाने वाला बजट, जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में आवंटित किया जाना चाहिए। दूसरा, अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित बजट लक्षित योजनाओं पर ही खर्च किया जाना चाहिए। तीसरा, अनुसूचित जनजाति के

लिए बनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित बजट की पूरी धनराशि, यानी 100 प्रतिशत धनराशि उसी कार्य पर खर्च की जानी चाहिए।

महोदय, आज देश का किसान महंगाई से मर रहा है। उसकी आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, बल्कि कृषि लागत चार गुना और बढ़ गई है। महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में 'गोधन न्याय योजना' के अंतर्गत 'गौठान योजना' चलाई जा रही है, जिससे किसान स्वावलम्बी हो रहे हैं। केन्द्र सरकार इस योजना को पूरे भारत में लागू करे ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके और उनकी आमदनी बढ़ सके।

महोदय, हमारे सामने वाले माननीय सदस्य एक बात कह रहे थे, अभी वे मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रही हूं, वे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में गृहमंत्री भी रह चुके हैं। वे नक्सलाइट प्रभाव वाले क्षेत्र की बात कह रहे हैं। महोदय, छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाके के आदिवासियों के प्रति निश्चित तौर पर हम सभी को संवेदनशील होना चाहिए। जिस तरह से आपने उनके लिए बजट बनाया और कटौती की, यह सही नहीं है। जो आदिवासी पहाड़ी इलाकों और जंगली इलाकों के कोने-कोने में रहते हैं, आज भी वे झरिये का पानी पीते हैं। बिजली की बात करते हुए वे बहुत जोर-जोर से कह रहे थे कि इस काम को केवल हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ही पूरा कर सकते हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि आपकी सरकार ने सात साल के समय में क्या किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जिस स्कूल से आप पढ़ कर आए हैं और आज यहां पर बैठे हुए हैं, वह कांग्रेस की ही देन है। एयरपोर्ट्स बनाये, यह कांग्रेस की देन है, आईटीआई, कॉलेज, स्कूल आदि ये सब कांग्रेस की देन है। इस बात को आपको भी सुनना पड़ेगा। **...(व्यवधान)**.. आपने नया क्या किया? मैं बात पर गहराई से चिंतन करती हूं, क्योंकि जब आपकी सरकार थी, तब छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसके चलते हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े-बड़े लीडर्स शहीद हुए, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हो रही है, आज तक केन्द्र सरकार एनआईए की रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं दे रही है। क्योंकि यह उस झीरम घाटी की बात है, जहां मैं मौजूद थी, मुझे भी गोली लगी थी, हैंड ग्रेनेड के छर्रे आज भी शरीर में पड़े हैं। मैं भी उस जगह से belong करती हूं, मैं एक आदिवासी महिला हूं। वहां के आदिवासी किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पीते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इस बारे में हमसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह बजट, जो आदिवासियों के हक का है, इसमें अकसर कटौती की जाती है। मेरा कहना है कि इस बजट में अब कटौती न हो, उनको बराबर उनका हक मिले और सौ प्रतिशत बजट आदिवासियों के लिए खर्च हो। उनके लिए पक्के घर बनें, उनके यहां पीने का पानी बराबर पहुंचे और बराबर बिजली पहुंचे। आपने कहा कि वहां बिजली हमने लगाई, जबकि वहां गांव-गांव में 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के तहत बिजली लगी है, गांव-गांव में पंचायती राज के माध्यम से विकास हुआ है। वहां के आदिवासी किस तरह से बमों के ऊपर महुआ पीते हैं, तेंदू पत्ता बीनते हैं, चिरौंजी बीनते हैं, यह वहां के लोग ही जान सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आदिवासियों का जो पूरा-पूरा हक है, वह उन्हें मिलना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्रीमती सम्पतिया उइके (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। सबसे पहले मैं इस बिल का समर्थन करती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : यह बिल नहीं है।

श्रीमती सम्पतिया उइके: ओह सॉरी, मैं इस अनुदान मांग का समर्थन करती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): यह मंत्रालय पर चर्चा है।

श्रीमती सम्पतिया उइके: हां, मैं इसे अपनी सहमति प्रदान करती हूं और साथ में हमारे माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं, जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने झारखंड के भोगता समुदाय की मांग पर विचार किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यह समुदाय बहुत लम्बे समय से लगातार मांग कर रहा था कि हमें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मैं इस नाते झारखंड क्षेत्र के उस समाज के समस्त भाई-बहनों और उस क्षेत्र के हमारे यशस्वी मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया।

महोदय, जिस तरह से मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे और छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी बहन बोल रही थीं, चूंकि मैं आदिवासी समाज से हूं, इसलिए उस समाज की चिंता हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं। मैं हमारे यशस्वी पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यह भाव लेकर आदिवासी मंत्रालय बनाया और सबसे पहले जनजातीय मंत्रालय में आदरणीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्री जुएल उरांव जी को केन्द्रीय मंत्री बनाया, जिसके कारण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी जनजातियों की चिंता की।

महोदय, अभी मैं एक माननीय सदस्य का भाषण सुन रही थी। मैं बताना चाहती हूं कि जब हम सुबह उठते हैं, तो सुबह उठकर सबसे पहले हम शौचालय के लिए जाते हैं और वे शौचालय बनाने का काम यदि किसी ने किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। हम यदि चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए पहले हम लोग चूल्हे का उपयोग करते थे। हम पहाड़, जंगल में रहने वाले वनवासी क्षेत्र के भाई-बहन हैं। परन्तु जिस तरह से हमारी बहन अभी भाषण दे रही थीं, मैं कहना चाहती हूं कि सबसे पहले यदि हम उपयोग करते हैं तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'उज्ज्वला योजना' के तहत गांवों में गैस देने का जो काम किया है, उसका उपयोग करते हुए हम लोग चाय पीते हैं। इतना ही नहीं जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने जनजातीय समुदाय के लिए चाहे वे स्वास्थ्य की सुविधाएं हों...

6.00 P.M.

अभी हमारे भाई सोलंकी जी कह रहे थे, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देखें, तो चाहे वह मध्य प्रदेश की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, आदिवासियों के लिए sickle cell नामक एक बड़ी बीमारी..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): One second. Now it is about 6 O' clock. So I will have to take the sense of the House for extension of the

Session till such period the hon. Member concludes her speech. ...*(Interruptions)*... Please continue.

श्रीमती सम्पतिया उइके : महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनजातीय समुदाय की चिन्ता जिस तरह से हमारी सरकार ने की, चाहे वह गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में वह लगातार काम कर रही है। इतना ही नहीं, यदि हम शिक्षा की बात करें, तो यह बिल्कुल कटु सत्य है कि 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार घड़ियाली आंसू बहाती रही और वोट बैंक की राजनीति करते हुए आदिवासियों के नाम पर लगातार वोट लेती रही, किन्तु आदिवासियों के लिए ऐसी कोई गम्भीर योजना नहीं बनायी, जिसके कारण हमारे जनजातीय समुदाय के लोग सिर्फ जंगलों और पहाड़ों में रह कर अशिक्षित ही रहे। अभी हमारे कुछ वक्तागण कह रहे थे कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग शिक्षित नहीं हो पाये। यह बात सही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब आदरणीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य विद्यालय पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों में, हर प्रदेश में लगातार बन रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, वहाँ हर ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय का निर्माण हो रहा है। वहाँ 89 ब्लॉक्स हैं, जहाँ 38 करोड़ रुपये से ये विद्यालय बन रहे हैं। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधान मंत्री जी और हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय मुंडा जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी। इतना ही नहीं, आज हमारे जनजातीय समुदाय की बेटियाँ एवं युवा देश-विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर बन यहाँ लौट कर आते हैं और इस देश को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कांग्रेस की सरकार ने महात्मा गांधी के नाम का लगातार उपयोग किया, किन्तु आज चाहे पूज्य महात्मा गांधी जी हों, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी हों या डा. अम्बेडकर जी हों, उनके कहे अनुसार, उनके मार्गदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का भाव लेकर लगातार काम कर रही है। उसके कारण आप और हम देख रहे हैं कि आज हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वे आदिवासी समाज के हों, दलित हों, पिछड़े वर्ग के हों, हर वर्ग के शोषित, पीड़ित व्यक्तियों के लिए सरकार लगातार योजनाएँ बना रही है और उन योजनाओं का लाभ हमारी सरकार अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कथन था कि अन्तिम छोर के व्यक्ति का भला होना चाहिए और इसीलिए आज हमारी सरकार यह काम कर रही है। इसके लिए मैं माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दे रही हूँ। आज जनता इस बात को समझ रही है।

लोग कहते थे कि हम आदिवासी समाज को सिर्फ नशे में डाल दें और उसको छूट दे दें, ताकि वे लोग शिक्षित न हों, जागरूक न हों और वे मूल धारा से नहीं जुड़ें। इस नाते वे इस तरीके की कोई योजना नहीं बनाते थे। उन्हें यही लगता था कि यदि आदिवासी समाज जाग जायेगा, तो फिर देश का क्या होगा? मैं पूरे साढ़े 12 करोड़ की जनता की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमारे आदिवासी समाज की चिन्ता की और आज उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया।

अभी मेरे भाई कह रहे थे - कोई बकरी चराता था, कोई तेंदु पत्ता तोड़ता था। महोदय, मैं भी एक साधारण परिवार से आती हूँ और इस नाते मैं भी तेंदु पत्ता तोड़ने का काम करती थी। हम लोग 4 बजे जंगल में जाते थे, वहाँ से तेंदु के पत्ते तोड़ कर लाते थे, उन्हें लाकर हम लोग पूरे दिन उनके गट्ठे बनाते थे और फिर उन्हें ले जाकर बेचते थे। हम लोगों की यह स्थिति थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने और यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने हमारी भावनाओं को समझा। उन्होंने हमारी भावनाओं को न सिर्फ समझा, बल्कि बोनस के रूप में उनको डबल कर दिया। उन्होंने हमें इस तरीके से सम्मान दिया कि आज तेंदु पत्ता तोड़ने का हक भी हमारे वनवासी समुदाय को दिया गया और तेंदु पत्ता तोड़ने से लेकर उनको बेचने तक का अधिकार वन समितियों को दिया गया। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसे वही समझ सकते हैं, क्योंकि वे इसे तोड़ते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने हम सब लोगों की लगातार चिन्ता की है, एक-एक परिवार की चिन्ता की है। ऐसे बहुत से परिवार थे, जिनके पास खाने को अनाज नहीं हुआ करता था, किन्तु कोविड के समय में 80 करोड़ परिवारों को, जिनमें 90 परसेंट परिवार हमारे जनजातीय समुदाय के थे, उनको फ्री में अनाज देने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत हर गरीब के घर तक राशन पहुँचाने का काम भी किया है। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, वहाँ अनाज पहुँचाने का यह काम भी हमारे प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हो रहा है। उपसभाध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी ने लगातार हम सब लोगों की, एक-एक परिवार की चिंता करते हुए कार्य किया। बहुत से ऐसे परिवार थे, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था, किन्तु vaccination के समय 80 करोड़ परिवारों को, जिनमें से 90 प्रतिशत लोग जनजातीय समुदाय के थे, उनको फ्री में अनाज देने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ। हमारे मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत हर गरीब के घर तक राशन पहुंचाने का कार्य किया है। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, वहां लगातार अनाज पहुंचाने का कार्य हमारे प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या पेयजल का क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। जब हम लोग जंगल, पहाड़ पर रहते थे, उस समय पीने के लिए पानी नहीं हुआ करता था। हम उस समय की सरकारों से पूछना चाहते हैं, जो यह कहते हैं कि हम आदिवासियों के शुभचिन्तक हैं, लेकिन उस समय हमारे आदिवासी समुदाय के लोग झिरिया, नदी और तालाब का पानी पीते थे। आज हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी की देन है कि जल शक्ति योजनाओं के तहत आज घर-घर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हमारे आदिवासी समुदाय के भाई-बहनों को जल की अच्छी सुविधाएं मिली हैं। हमने देखा है कि जब पूर्व में 'इंदिरा आवास योजना' चलती थी, उस समय छः, बारह और बीस हजार रुपए दिये जाते थे और जैसे एक मुर्गी के लिए छोटी सी झोंपड़ी बनाई जाती है, इस प्रकार से वह आवास बनता था, किन्तु आज मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1 लाख 60 हजार रुपए देने का काम किया, जिससे आज उनको एक अच्छा चमचमाता हुआ मकान मिल रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। आप लोग हर योजना में अपने नेताओं का नाम रखते थे, चाहे वह इंदिरा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों या राजीव गांधी हों। मैं

हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि वे सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास लेकर काम करने वाले हैं। उन्होंने कभी अपने नाम से कोई योजना नहीं चलाई और माननीय प्रधान मंत्री की योजना का नाम चलाकर वे काम कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' का शुभारंभ किया। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि जंगल, पहाड़ तक प्रधान मंत्री सड़क बनी, जिसके कारण हमारे आदिवासी, जनजातीय समाज के लोगों को रोजगार और मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिला। आज हमारे आदिवासी भाई-बहन, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, बिज़नेस का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्हें आगे आने का मौका मिला है। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। आज आप लोग बिजली की बात कर रहे हैं, जब यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने 2014 में शपथ ली थी, तो उस समय उन्होंने लाल किले से ध्वजारोहण करते समय कहा था कि हम अंतिम छोर में रहने वाले उन भाई-बहनों की, जो कि दलित-पीड़ित वर्ग के हैं, चिंता करेंगे और जहां बिजली नहीं है, वहां हम बिजली लगायेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 'सौभाग्य योजना' के तहत 3 करोड़ से अधिक परिवारों के घर में बिजली लगाने का काम भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया। हर क्षेत्र में नेटवर्क बना रहे, ताकि हमारे युवाओं को नेटवर्क और society से जुड़ने का अवसर मिल सके, उस क्षेत्र में हमें लगातार काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। जैसा कि हमारे भाई कह रहे थे कि पूरे विश्व में सबसे एक नंबर का रेलवे स्टेशन यदि बना है, तो वह रानी कमलापति के नाम से बना है, उसे यह नाम मध्य प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया और वह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो माननीय प्रधान मंत्री जी की देन है। उसका पूरा श्रेय माननीय प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को जाता है। हमारे कांग्रेस के एक नेता, जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, वे छिंदवाड़ा के रहने वाले थे, जहां के सभी blocks आदिवासी blocks हैं, लेकिन उन्होंने आदिवासियों के नाम से एक भी योजना नहीं बनाई और योजना नहीं बनने के कारण वहां के लोग सभी लाभों से वंचित रहे। लेकिन जब हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी वहां गये, तो मुख्य मंत्री जी ने वहां छिंदवाड़ा महाविद्यालय का नाम शंकर शाह के नाम पर रखा।

उपसभाध्यक्ष जी, आज आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और मेडिकल कॉलेज भी माननीय प्रधान मंत्री जी की देन है। उन्होंने हर आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, जिसके तहत मंडला में एक मेडिकल कॉलेज बना, जिसके कारण आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं और आज हर आदिवासी, बच्चा-बच्चा, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की अगवाई कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा आदिवासी समाज, पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती सम्पतिया उइके: अभी हमारे भाई कह रहे थे कि मैं दिल पर हाथ रख कर कह रहा हूँ कि आज जनजातीय समाज में रहने वाला हर व्यक्ति यदि किसी को भगवान के रूप में मान रहा है, तो

वह आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी हैं। वे आदिवासियों के मसीहा बन कर, भगवान बन कर आदिवासी समाज के भाई-बहनों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MESSAGES FROM LOK SABHA - *Contd.*

Regarding nomination of members to the Committee on Welfare of Other Backward Classes

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from Lok Sabha, signed by the Secretary-General of Lok Sabha.

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Tuesday, the 15th March, 2022, adopted the following Motion:-

> "That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to elect ten members from amongst the Members of the Rajya Sabha to associate with the Committee on Welfare of Other Backward Classes for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the Committee and do communicate to this House the names of Members so elected to the Committee."

I am to request that the concurrence of Rajya Sabha in the said Motion, and also the names of the Members of Rajya Sabha so elected to the said Committee, may be communicated to this House."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Wednesday, the 16th March, 2022.

The House then adjourned at eleven minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 16th March, 2022.